

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 मार्च 2010

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूचि

बुधवार, 10 मार्च, 2010

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नो के उत्तर	(4)22
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(4)32
विभिन्न विशयो का उठाया जाना	(4)32
वर्ष 2010–2011 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना	(4)34

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 10 मार्च, 2010

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री हरमोहिन्द्र सिंह चटठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर, अब सवाल होंगे।

Collection of Revenue from Mineral Quarries

***156. Shri Sampat Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the total revenue collected from minor mineral stone quarries during the financial year 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-2010 year wise together with the number of such quarries in the State?

P.W.D (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, the year wise revenue collected from minerals in the State and revenue collected from minor mineral "stone" quarries with number of such stone quarries operated is as under-

Year	Total Revenue collected from Minerals	Revenue collected from stone quarries	Number of stone quarries operated
------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

2005-06	153.34	114-.49	294
2006-07	136.26	105.33	299
2007-08	215.70	156.99	176
2008-09	195.24	144.72	169
2009-10	226.00	160.62	196
* upto Jan, 2010			

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूँ कि इन्होंने खनिज माफिया को खत्म किया है। यह सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सर, जहां तक स्टोन क्वैरिज के नम्बर्ज है इसमें हमारी कलैव 100 और भी हो सकती थी। स्टोन क्वैरीज 294 से घटकर 196 ही रह गई है, यानि 100 क्वैरीज घट गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ने पूछना चाहता हूँ कि इन क्वैरीज के घटने के क्या कारण है? दूसरे मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि आज बाद हरियाणा प्रदेश में सभी क्वैरीज चाहे वह माईनर की है या मेजर माईन्ज की है, वे बंद हो चुकी है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 3 सवाल पूछे हैं। एक तो मई से दिसम्बर 2002 के बाद आनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसके बाद सब-स्टोन क्वैरीज except for two mines, एक सरोही में और एक

खौरी जमालपुर डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद मे हि जिनकी 5 फरवरी, 2009 तक नार्मल कोर्स आफ लीज है तब तक चलाने की इजाजत थी, बाकी की सब बंद कर दी गई थी। उसके बाद लास्ट आर्डर है जिसके बारे मे जाने के लिए माननीय सदस्य ने पूछा है। सर, ऐक्टिविटीज स्टोन और अदर मिनरल्ज की सारी माइनिंग 28 जनवरी, 2010 से अपने प्रान्त के राजस्थान स्टेट पर भी इसी प्रकार की पाबन्दी लगा दी है। तीसरे सर, इन्होने पूछा है कि आगे हम क्या करने वाले है? उसके बारे मे इनको बताना चाहूंगा कि सैन्ट्रली इम्पावर्ड कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है जिसको हम सी ई सी कहते है उसके साथ मई और जून 2008 में कुछ इ लूज के उपर कंसैल्ट हुई है क्योंकि दिल्ली के चारो तरफ जो स्टेटस है वि ोशतौर पर राजस्थान और हरियाणा उनको सुप्रीम कोर्ट लगातर मोनिटर करती है और हमसे बात करके इस बारे मे निर्णय करती है। इसकी आखिरी मीटिंग 7 जनवरी, 2009 को हुई थी और उसके बाद आनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट आफ हरियाणा को कंस्टान मैटीरियल माईनर मिनरल के लिए डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद मे 600 हैक्टेयर मे करने की इजाजत दी है। Vide orders dated 8th October, however, Sir, there is a condition attached to it that the actual mining can commence only with the simultaneous commencement of work on restoration and rehabilitation of the old mines. We have already engaged consultants for preparation of a details rehabilitation and restoration plan. Sir, hopefully this shall be ready by 31st March, 2010. We will have to submit it to centrally Empowered Committee as the Supreme Court has directed. Then it will be

sent to the MoEFs i.e. Ministry of Environment Forests for their approval. Once they will approve it then that it will go to the Supreme Court then they approve it. Ten only it can start. Sir, I also want to tell the Hon'ble Member with your permission that Supreme Court has agreed in principal to consider mining over an area of 1500 acres in district Gurgaon and Mewat but Sir, no final approval has come. It will only be given after assessing the compliance of prescribed norms in respect of the earlier portion in the Faridabad Court.

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने डिटेल मे रिप्लाइ दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बंद क्यों की? इनका जो फारेस्ट का डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट का डिपार्टमेंट है और माईन्स का डिपार्टमेंट है क्या इनके कोओर्डिनेशन की कमी की वजह से मिनिस्ट्री आफ फारैस्ट एंड एन्वार्यमेंट, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दो नोटिफिकेशन इ यु की। एक बार माईनर मिलर्री आफ फारैस्ट एंड एन्वार्यमेंट, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दो नोटिफिकेशन इ यु की। एक बार माईनर मिलरल्ज की और दूसरी बार मेजर मिनरल्ज की। उनकी नोटिफिकेशन आयी कि अगर आपकी पांच हैक्टेयर से उपर की क्वैरी है तो आपको उनसे क्लीयरेंस लेने की जरूरत है, और अगर इससे नीचे की है तो फिर उन दोनो विभागो से क्लीयरेंस लेने की जरूरत नहीं है। सर, उसके लिए प्रोजैक्ट बनाकर और प्लान बनाकर देना था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वह प्लान बनाकर दी? सर, दोनो बार यह प्लान न देने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन माईनर को बंद किया। स्पीकर सर, दूसरा सवाल मैं मंत्री महोदय

से यह पूछना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट का या औफिसर्ज का जो लैक्लस्टर एटीच्यूट रहा, क्या वह उसकी भी देखभाल करेंगे कि किस कारण से बंद की गयी है? सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको बंद किया है वह एनवार्यमेंट मिनिस्ट्री की क्लीयरेंस न देने की वजह से बंद किया है। सर, इसके अगेन्सट जो काम किया वह यह किया गया कि प्लान बना दिए गए और कह दिया गया कि पांच हैक्टेयर से या उससे भी कम के प्लाट दे दें और वह दे दिए गए। इसके बावजूद एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा क्लीयरेंस न होने की वजह से वह बाद में बंद हो गयी। सर, बार बार इस तरह से एस्क्रेप रुट ढूँढने के बजाए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्यों नहीं इकटठे होकर कोआर्डिनेशन करके एनवार्यमेंट मिनिस्ट्री ने जो इनको गाईडलाइन्स दी है उसके मुताबिक काम करते? अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे स्टेट के रैवेन्यू का लौस भी होगा और हर चीज महंगी भी मिलेगी। अब जब हरियाणा प्रदेश में माईनर और मेजर दोनो मिनरल्स माईज बंद हो गयी है तो इस स्थिति के अंदर हरियाणा में जो लोग मकान बनाते हैं या सरकार कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करेगी तो क्या यह मैटीरियल मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो यह बाहर से लाना पड़ेगा? अगर यह बाहर से लाएंगे तो क्या यह महंगा नहीं मिलेगा?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। चार पांच प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। इनकी जो जिज्ञासा है और जो इनके प्रश्न हैं उसके बारे में प्रान्त

के लोग भी जानना चाहते हैं। जो चौधरी सम्पत सिंह जी ने प्र न पूछे हैं उनका सक्षिप्त समय में मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। एक बात इनकी वाजिब है कि माईनिंग ऐक्टिविटीज बंद होने से प्राकृतिक तौर पर कंस्ट्रक्शन मैटीरियल की कीमत उपर जाती है। इन्होंने माईन्स रैवेन्यू की चर्चा की है। मैं अपना जवाब भी सबसे पहले वही से भुरु करना चाहूंगा। सर, चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा जी की सरकार ने एक ट्रांसपेरेन्ट माईन्स ऑक्शन पालिसी की हरियाणा प्रदेश के अंदर भुरुआत की। यह बात सच है और चौधरी सम्पत सिंह को भी मालूम है कि एक समय ऐसा था कि जब कुछ विरोध विपक्षी दलों की सरकार हरियाणा के अंदर थी तो उस समय कुछ चहेते लोगों को एक विरोध तरीके से माईन्स दे दी जाती थी। यह बात आंकड़ों के अंदर भी रिफ्लैक्टड है। सन् 2000-01 से लेकर 2004-05 के बीच पांच सालों में माईनज का कुल रैवेन्यू 536 करोड़ 7 लाख रुपये था। मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य और सदन को विरोध तौर से दो साल के आंकड़े देना चाहता हूँ। 2003-04 के अंदर माईनज का कुल रैवेन्यू केवल 77 करोड़ 67 लाख रुपये था, 2004-05 में जब मेरे काबिल साथी जो हमारे सामने बैठे हैं, इनकी सरकार गयी और आखिर में जब इनकी सरकार का साल था उस समय माईन्स का 92 करोड़ 4 लाख रुपये रैवेन्यू आया। चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार मार्च, 2005 में आई और उसके बाद यह रैवेन्यू मात्र एक वर्ष में 92 करोड़ 4 लाख से बढ़कर 153 करोड़ 34 लाख रुपये आया। यह सोचने की बात है। (विधन) सन्

2006-07 में वह थोड़ा घटकर 136 करोड़ 26 लाख रुपये हो गया जो कि तकरीबन 15 करोड़ रुपये कम आया। 2007-08 में 215 करोड़ 70 लाख रुपये हो गया और वर्ष 2008-09 में क्योंकि 28 फरवरी, 2009 के बाद माईनस बंद हो गई इसलिए रैवेन्यू 195 करोड़ 24 लाख रुपये आया और जनवरी 2010 में 226 करोड़ रुपये रैवेन्यू आया। It is all time high Sir, यानि कि हमारे पांच साल के कार्यकाल में 926 करोड़ रुपये रैवेन्यू आया। चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा के नेतृत्व वाली सरकार माईन्ज से इतना ज्यादा रैवेन्यू हरियाणा के आज जनमानस की भलाई के लिए लेकर आई, जो कि सरकार की मं ता को कही न कही बताता है। मेरे काबिल साथी ने 3-4 बड़े ही वाजिब सवाल उठाये हैं यह सच है कि जैसे ही माईनज का रैवेन्यू बढ़ा। (विधन)

श्री अ लोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, यह कवै चन आवर है इसमें कवै चन का जवाब दें, भाशण न दें। (विधन)

Mr Speaker: Is it the way Arora Sahib? वे जवाब ही दे रहे हैं। (विधन)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैं माननीय सदस्य संपत सिंह जी की सप्लीमेंट्री का जवाब दे रहा हूँ। He has asked it in his supplementary and I am answering that. सर, कई बार जब

किसी की पोल खुलती है तो पीडा होती है उसका मेरे पास कोई हल नहीं है। मुझसे यह सवाल पूछा गया था कि क्या माईन्ज बंद होने से कंस्ट्रक्शन मैटीरियल की कास्ट बढ़ जायेगी तो इसमें मेरा जवाब है कि हां सर, माननीय उच्चतम न्यायालय इस बात को खुद मोनिटर करता है और उनके लेटेस्ट आर्डर है और उन्होंने हमारे प्रदेशों के साथ कोई डिपार्टमेंट्स की माईनिंग भी बंद की है। माननीय सदस्य ने यह भी जाने की कोशिश की कि क्या कोई डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की कमी रही है या एक इलाक़े से ज्यादा समय तक क्या प्रोपर माईनिंग नहीं की गई, ये दो तीन बातें रेंज की गईं और मेरा इसके बारे में जवाब है कि पूरा जो दिल्ली के आसपास अरावाल का इलाका है, इसमें कई सारी फैक्टर होते हैं, हम किसी एक फैक्टर को पिन प्वायंट तो कर नहीं सकते। पूरे अरावली का जो इलाका है उसके बचाने के लिए और दिल्ली के चारों तरफ के तीनों राज्यों हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इकोलोजी को गेटमेन करने का सतत प्रयास सुप्रीम कोर्ट का है और एक्सपर्ट्स इसको देख रहे हैं। माननीय सदस्य ने यह भी जाने की कोशिश की कि हरियाणा सरकार इसके लिए क्या कारगर कदम उठायेगी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 9 डिफरेंट स्टैप्स हरियाणा की मौजूदा सरकार ने लिये हैं। मैं आपकी अनुमति से सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि क्या क्या लॉग टर्म मेजर इन्फोवर्ड कमेटी के अलावा हम ले रहे हैं वे स्टैप्स पढ़कर बताना चाहूंगा, इसमें लिखा है कि

“it is for the first time that any State has taken up a holistic approach to address the concerns arising on account of mining operation on a long term basis. The State Governmnet has taken a number of important decisions in this direction. These are:

i) A decision was taken at the level of Council of Ministers in its meeting held on 21.8.2009 to ban mining of major minerals in the districts of Faridabad and Mewat for a period of 10 years.

ii) A decision to undertake State controlled mining of construction material over a li8mited area of 600 hectares in the district of Faridabad out of total mineral bearing area of 6700 hectares, and 1500 hectares in the district of Gurgaon and Mewat of the total mineral baring area of approximately 23000 hectares following extensive discussion and consensus with the CEC;

iii) Notified a ‘ Scheme of Mining’ for the district of Gurgaon and Mewat (which will also be extended to district of Gurgaon and Mewat) consisting of the detailed guidelines for grant of mining contract/leases, establishment of an “Aravalli Rehabilitation Fund” and constitution of a Monitoring Committee to monitor that the mining operations over the limit4d areas are carried out in compliance of the EMPs for these areas;

श्री अध्यक्ष: बस, काफी लम्बा जवाब हो गया। इतना ही काफी है।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, then you can ask the Member to come to me because he wanted to know.

Smt. Kiran Choudhary: Hon'ble Speaker Sir, I would like to ask the Hon'ble Minister that the 600 hectares which have been said the Haryana Government will be identified for mining purposes, have those been identified yet or not? Secondly, what action is being taken for the water depletion that is happening in such a fast pace because of these mining activities, the while of the water table has gone down drastically. So, what steps are taken by the Government to ameliorate that. The workers in Tosham and Dadri. What measures are going to be taken by the Government to rehabilitate those mine mazdoors and labourers because their rozi-roti, their entire livelihood is dependent upon that.

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, since you are permitting that Member to ask four four questions in one supplementary then I will have to give long answers. As far as the first question of the Hon'ble Member is concerned, I want to say that the initial area that been identified but the identification is subject to clearance by the Centrally Empowered Committee that has been appointed by the Supreme Court then it goes to the Minister of Environment and Forests. Finally, it is submitted to the Supreme Court, Once they give the clearance then only an area is deemed to be cleared. As far as second and third questions are concerned, they are separate questions and a separate notice needs to be given.

श्री अ गोक कुमार अरोडा: स्पीकर सर, मंत्री जी ने बडे विस्तार से बताया है कि रैवेन्यू बढा है। मेरा मंत्री जी से इसी बारे मे सवाल है। एक तो मंत्री जी यह बताये कि वर्ष 2000 से पहले कितना रैवेन्यू आता था? दूसरे आज महंगाई की मार पड रही है और सरकार पैसा कमाने के लिए नहीं होती। पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार होती है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो रेत का ट्रक पहले 2500 रुपये मे मिलता था आज वह 11000 रुपये में मिलता है और बजरी का ट्रक जो पहले 3500 रुपये मे आता था आज वह 14000 रुपये मे आता है।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, this is a separate question. So, a separate notice needs to be given. (Interruptions)

श्री अ गोक कुमार अरोडा: स्पीकर सर, यह इसी से जुडा हुआ प्र न है, मंत्री जी स्टेट रैवेन्यू की बात कर रहे है। यह प्र न सैप्रेट थोडे ही है। मंत्री जी खुद बता रहे है कि इतना रैवेन्यू बढा है। यह प्र न भी इसी प्र न से जुडा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: यह मामला प्राइस से जुडा हुआ नहीं है।

श्री अ गोक कुमार अरोडा: स्पीकर सर, मंत्री जी यह बताये कि कितना रैवेन्यू बढा है? महंगाई की मार तो लोगों पर पड रही है। (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल गुर्जर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदे 1 थे तभी ये खाने बंद की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदे 1 के बाद अभी तक खानो में कितनी चोरी हुई है, कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं इस बारे में मंत्री जी बताये? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदे 1 दिए उसके बाद फोरैस्ट एरियाज में पिछले पांच साल में सुप्रीम कोर्ट के आदे 10 कि अवहेलना कितनी हुई है और अवैध निर्माण गुडगांव और फरीदाबाद में फोरैस्ट एरिया में कितने हुए हैं? इस बारे में मंत्री जी बतायें।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, this is also a separate question. So a separate notice needs to be given.

श्री बिहान लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो ये रेती और बजरी के ठेके दिये जाते हैं उससे सरकार तो ठेकेदार से पैसा ले लेती है और ठेकेदार उस रेते और बजरी से पैसे कम लेता है लेकिन जिस किसान की जमीन से वह रेता उठाया जाता है उसको क्या मिलता है इस बारे में मंत्री जी बतायें।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, this is also a separate question. So a separate notice needs to be given.

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया था उसका जवाब नहीं आया इसलिए मैं वही सवाल करने जा रहा

हू। मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से आर्डर देना पडा था। इन्वायरमेंट मिनिस्टर की क्लीयरेंस नहीं ली हुई थी। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की वायले इन डिपार्टमेंट कर रहा था। क्या उसी की वजह से तो ये क्वैरीज बंद नहीं हुई, मैंने पहले पूछा था। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक माइनर माइनिंग के लिए और एक मेजर माइनिंग के लिए नोटिफिके इन 14 सितम्बर, 2006 को और एक उससे पहले 1994 मे हुई थी। उस समय जो ये दोनो नोटिफिके इन हुई थी क्या उसके बाद सरकार कोई पालिसी नहीं बना सकती थी? इतना लम्बा पीरियड हो गया लेकिन कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। मैं यह कह रहा था कि इसमे डिपार्टमेंट के कोओर्डिने इन की कमी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के साथ कोओर्डिने इन करके कितनी जल्दी ये पालिसी बनायेंगे। हमारी सरकार आने के बाद रैवेन्यू बढा है इसमे कोई दो राय नहीं लेकिन जो 100 क्वैरीज बंद हुई है अगर ये बंद न हुई होती तो रैवेन्यू और बढ जाता।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: माननीय सदस्य की जिज्ञासा और चिंता दोनो वाजिब है। यह सच है कि पिछले एक से डेढ द एक मे जब ये माईनज चालू की गई थी तो इनवायरमेंट क्लीयरेंस नहीं थी। ये सारी नोटिफिके इन जो समय समय पर जारी हुई है उनका सम्पूर्ण निर्वहन नहीं हो पाया था। इसलिए मैं बता रहा था, जब आपने कहा कि हरियाणा सरकार ने अब एक

होलिस्टिक पॉलिसी बनाई है उसमें हमने 9 भिन्न भिन्न कदम उठाए हैं। मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा, इस बारे में एक माननीय सदस्य ने प्रश्न भी पूछा था हालांकि यह पृथक प्रश्न है कि अगर कोई लैंड आनर है तो और अगर उसकी जमीन जाती है तो 10 परसेंट लीज अमाउंट या जो कम्पन गेसन जमीन का मालिक लीज होल्डर्स से सैटल करे, चाहे 100 की 100 परसेंट ही सैटल कर ले वह उसको जाती है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन दोनों नोटिफिकेशन के इम्प्लीमेंट का सवाल है तो हमने जो होलिस्टिक एप्रोच बनाई है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रली इम्पावर्ड कमेटी निर्धारित है जिसके मुताबिक ग्रीन बैंच निर्णय करता है। हर वह प्रोजेक्ट जो हम बनाएंगे चाहे वह 600 एकड़ का प्रोजेक्ट बनाए और चाहे 1500 एकड़ का बनाएं, उन सबके केस सेंट्रली इम्पावर्ड कमेटी और मिनिस्ट्री आफ एन्वायरमेंट एण्ड फोरैस्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जब वहां से फाइनली क्लियरेंस मिल जाएगी, उसके बाद ही उस पर माइनिंग सम्भव हो पाएगी। (विधन)

डा० अजय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सरकार के काबिल मंत्री ने रैवेन्यू को बढ़ाने के आंकड़े हाउस के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने रैवेन्यू बढ़ाया है यह बहुत बढ़िया बात है। सरकार धन कमाने के लिए नहीं होती बल्कि लोगों के हितार्थ काम करने के लिए होती है। आज हजारों लोग रोजी रोटी को महरूम हो गए हैं। हजारों लोगों के बीवी बच्चे भुखे मर रहे हैं। हजारों लोगों के

बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहता हूँ कि जो क्वैरीज बंद हुई है उनमें काम करने वाले मजदूरों के लिए भी सरकार ने कोई बंदोबस्त किया है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पहले ही श्रीमती किरण चौधरी जी ने पूछा है। अजय चौटाला जी भी वही प्रश्न दोहरा रहे हैं। माईनज के वर्क्स की रिहैबिलिटेसन पृथक प्रश्न है। माननीय सदस्या जैसे ही यह पृथक सवाल पूछेंगी हम पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सदन में प्रस्तुत करेंगे। माननीय किरण चौधरी जी ने जो चिंता जाहिर की है, अजय जी ने उसको दोहराया है उसके साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। हमें मालूम है कि गरीब मजदूर की रिहैबिलिटेसन आवश्यक है परंतु ये सारा डाटा इस सवाल से सीधा जुड़ा नहीं था इसलिए उपलब्ध नहीं है। आप लिखकर मेरे पास भिजवा दें, अजय सिंह चौटाला भी मेरे पास लिखकर भिजवा देंगे, मैं इनको लिखकर जवाब भिजवा दूंगा।

Construction of New Road

***18 Shri Krishna Lal Panwar:** Will the P.W.D (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a new road from Villages Sutana, Distt. Panipat to Thermal Plant upto Assandh Road; if so, the time by which the said road is likely to be constructed?

P.W.D (B&R) Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala): No, Sir.

श्री कृष्ण लाल पंवार: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस जवाब पर ये पुनर्विचार करें क्योंकि सुताना गांव के साथ में थर्मल प्लांट की 700 एकड़ जमीन में ऐ 1 डैक है। थर्मल प्लांट की सारी ऐ 1 पानी के साथ मिक्स होकर वहां पर स्टोर होती है। वहां पर किसान सेम की समस्या से तो पहले ही प्रभावित है। सुताना गांव के किसानों को मतलौडा मण्डी में अपनी फसल को 10 की0 मी0 घुमकर ले जानी पड़ती है। यदि यह डेढ़ कि0 मी0 का टुकड़ा बना दिया जायेगा तो उनका 10 कि0 मी0 का चक्कर बच जायेगा। इसी गांव की 700 एकड़ जमीन थर्मल प्लांट में भी एक्वायर हो रखी है। अब की बार पैडी सीजन में ऐ 1 डैक लीक होने के कारण वहां के किसानों की पैडी की फसल बह गई थी। मेरी मंत्री जी से पुनः प्रार्थना है कि इस सड़क को बनाने पर आप पुनर्विचार करें ताकि वहां के लोगों का 10कि0 मी0 का चक्कर बच जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पंवार साहब की भावनाओं की कद्र करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ने 1 नल हाई वे 1 पर संजय चौक पानीपत के बिलकुल साथ से गुजरने वाली सड़क से सुताना गांव कनेक्ट होता है। हमने एक सड़क ने 1 नल हाई वे 1 और दूसरी पानीपत जींद

रोड जो स्टेट हाई वे 14 है यानि संजय चौक और स्टेट हाई वे 14 है उसे आलरेडी प्राइम मिनिस्टर ग्राम सडक योजना के फेज 8 मे मंजुर करवा लिया है, जिसकी लैथ 15.3 कि० मी० है। इस सडक का कंट्रक्ट दे दिया गया है और मौके पर काम भी चल रहा है। इस सडक पर 970 लाख रुपये का खर्चा आएगा और यह सडक अप्रैल 2010 तक बनकर तैयार हो जायेगी। इस सडक के बनने के बाद फिर भी अगर सुताना गांव के निवासियो को और माननीय सदस्य को लगेगा कि अभी भी तकलीफ है और यह सडक बननी चाहिए तो इस बारे में माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूरी लेकर इस पर विचार कर लेंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब मे बताया है कि प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के तहत वहां दूसरी सडक बनाई जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आप जिस सडक को बनाने की बात कर रहे है वह दूसरे गांवो लुहारी आदि होते हुए मतलौडा निकलती है। मैं तो सुताना से थर्मल प्लांट तक की सडक बनाने के लिए कह रहा हूं जो पानीपत से सफीदो रोड है, उस रोड से मिलाती है और सीधा मतलौडा चली जाती है। इस सडक के बनने से सुताना गांव के लोगो का मतलौडा मण्डी तक 10 कि० मी० का रास्ता कम हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जिस सडक का जिक्र कर रहे है उसका इस सडक से

कोई ताल्लुक नहीं है मैं तो केवल डेढ कि० मी० की सडक सुताना से थर्मल प्लांट तक बनाने की बात कर रहा हूँ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जो सडक प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के तहत बनाई जा रही है उसी पर सुताना गांव भी पडता है। माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुडडा जी की सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत इस सडक को बना रही है और इस पर 970 लाख रुपये खर्च होंगे। इस सडक के बनने के बाद अगर सुताना गांव के निवासियों के लिए और माननीय सदस्य को फिर भी लगेगा कि अभी भी तकलीफ है और यह सडक बननी चाहिए तो इस बारे में माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे देंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूरी लेकर इस पर विचार कर लेंगे।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में बहुत सी ऐसी सडके हैं जो बिना निदान के बनाई हुई हैं। (विधन)

श्री अध्यक्ष: रामपाल माजरा जी, प्लीज आप बैठें। आपका यह सवाल रैलवैंट नहीं है। माजरा साहब, आप इतने सीनियर मैम्बर हैं और सवाल भी रैलवैंट नहीं कर रहे। प्लीज आप बैठें

Construction of Swimming Pool

***137. Dr Hari Chand Midha:** Will the Chief Minister be pleased to state whether any announcement to construct a swimming pool at Jind was made by the Hon'ble Chief Minister five years ago; if so, the time by which the said swimming pool is likely to be constructed?

P.W.D (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Yes, Sir, However, the announcement for constructing the swimming pool at Jind was made on 1/1/2007 and not five years ago.

The swimming pool is expected to be constructed within a period of two years.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि हमने अपने जवाब में तो बताया है कि दो साल के अंदर यह स्विमिंग पूल बना देंगे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यह स्विमिंग पूल इसी साल 2010-11 तक बना दिया जायेगा।

डा० हरिचन्द मिड्डा: स्पीकर सर, मैं जवाब से संतुष्ट हूँ।

Maintenance of War Memorials

***65. Col. Raghbir Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal to allocate funds separately for the maintenance and upkeep of War memorials installed at various places in the State; if so, the details thereof?

P.W.D (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Yes Sir, expenses on maintenance and upkeep of War Memorials are being met from Haryana Defence and Security Relief Fund.

A sum of Rs. 1940088/- has been spent on maintenance and upkeep of War Memorials from Haryana Defence and Security Relief Fund so far.

कर्मल रधुबीर सिंह: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरा सवाल यह था कि क्या वार मैमोरियल के लिए कोई सैपरेट फण्ड सरकार ने बताया है। यह मैं भी जानता हूँ कि अभी तक वार मैमोरियल हमारे उन वार मैमोरियल का मैंटीनेंस डी एस आर के माध्यम से किया जाता है। स्पीकर सर, वार मैमोरियल उन पर वार हीरोज की याद में बनाये जाते हैं जिनकी वजह से आज हम आजादी की हवा में सास ले रहे हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनके अप कीप और मैंटीनेंस ऐकस्ट्रा आर्जिनरी होने चाहिए जब कि ऐसा नहीं है। क्या मंत्री जी कृपा बतायेंगे कि सरकार इसके लिए क्या अरेंजमेंट्स करने जा रही है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, माननीय कर्मल साहब ने हरियाण डिफेंस और सिक्योरिटी रिलीफ फण्ड के बारे में पूछा है। स्पीकर सर, पंजाब डिफेंस एण्ड सिक्योरिटी रिलीफ फण्ड, 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तब बन गया था और यह रजिस्ट्रार आफ फर्म्ज एण्ड सोसायटी के पास रजिस्टर्ड है।

हमारे पास इसके अंदर सफ़ी एंट पैसा अवेलेबल है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी अनुमति से जो पैसा खर्च किया है उसकी जानकारी पूरे सदन और कर्नल साहब को दे दी है। मैं माननीय सदस्य को यह आवासन देना चाहूंगा कि इस ट्रेड के उपर जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, और जिन्होंने ट्रेड की सेवा की है, चौधरी भुपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार की ये पहली प्राथमिकता है। इसके बावजूद भी अगर कहीं पर माननीय सदस्य को कोई कोताही का इंस्टांस मिला, आप कीप में या मॉन्टिंग में तो उसे वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को या मुझे लिखकर भेजें। मैं इनको आपके माध्यम से आवासन देता हूँ कि एक निर्धारित समय सीमा में हम उसको दुरुस्त करवाकर माननीय सदस्य को लिखित रूप में इस बारे में जानकारी भेजेंगे।

कर्नल रघुबीर सिंह: स्पीकर सर, मैं सरकार से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है वह एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सोल्जर बोर्ड ने मुझे एक चिट्ठी लिखी है। मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।

“Bhiwani is the Biggest district in terms of strength of Ex-servicemen and area. The district also pioneers when it comes to Warriors and gallantry awards which is a matter of pride for one and all in the district. Every district has a war memorial to commemorate the heroes of the society and the district. Regretably the war memorial at Bhiwani is not befitting the sacrifices made by its heroes.”

स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी प्रपोजल है कि भिवानी के वार मैमोरियल स्माकर को दोबारा से बीफिटिंग मैनर में नया बनाया जायेगा क्योंकि जो आज का वार मैमोरियल स्माकर है वह ऐसी जगह पर है जहां पर उसकी न तो कोई मैनटेनेंस करता है और न ही उसे कोई देख सकता है। वार मैमोरियल हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भिवानी के अंदर नया मैमोरियल स्माकर बनाने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, मैंने केवल भिवानी के बारे में नहीं अपितु पूरे हरियाणा के लिए माननीय कर्नल साहब को on the floor of the House. कैटेगरीकली आ वासन दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अगर वे इस बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे या माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखकर भेज दें। जो भी दुरुस्ती ये चाहते हैं, जिस प्रकार की भी ये तरमीम सरकार से चाहते हैं, अगर उसके लिए ये कोई स्पैसिफिक डिजाईन चाहते हैं, कोई स्पैसिफिक मैटीरियल इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, कोई स्पैसिफिक एक्सपेंसन्स ये चाहते हैं, कोई स्पैसिफिक गैलरी उसमें क्रीएट करवाना चाहते हैं और उसके अंदर कोई स्पैसिफिक चीज बनवाना चाहते हैं तो हम उसे सिम्पेथेटिकली

कंसीडर करके एक निर्धारित समय सीमा में बनाकर और उसका जवाब आपको लिखित रूप में देंगे।

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, 1857 की जो लडाई लड़ी गई थी वह अम्बाला छावनी से भुरु हुई थी जब वहां पर उसकी 150वीं जयन्ती मनाई जा रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग सभी मंचों से यह घोषणा की थी कि 1857 की क्रांति के जिन भाहीद वीरों के बारे में कुछ नहीं किया जा सका उनकी याद में अम्बाला छावनी में हम एक स्मारक बनवायेंगे। उसके बाद कुछ मंत्रियों ने भी इस प्रकार की घोषणाएं की। कुमारी भौलजा, माननीय केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार ने मेरी मौजूदगी में एक दिन यह कहा था कि वे इस स्मारक के लिए पांच लाख रुपये देंगे लेकिन आज तक पांच रुपये भी सरकार द्वारा इस स्मारक के नाम पर खर्च नहीं किये गये हैं। स्पीकर सर, जैसा अभी हमारे काबिल मंत्री बता रहे थे कि हमारी सरकार इस बारे में बहुत ज्यादा संजीदा है। इस मामले में तो सरकार बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आती या तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा को बिल्कुल भूल गये या फिर प्रशासन उनकी घोषणा को गंभीरता से नहीं ले रहा।

अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानियां दी हैं उस बात को ये सीरियसली न लेकर मजाक में ले रहे हैं यह गलत बात है। हंसी मजाक में उड़ाना उनका अपमान करने के समान है सर। जिन्होंने हमारे देश की आजादी की लडाई की

भुरुआत की, जिन्होंने कुर्बानियां दी, (गोर एवं व्यवधान) This is a serious matter. We should take it seriously.

श्री अध्यक्ष: विज साहब, मैं आपकी बात को मानता हूँ कि सीरियसली लेना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान) आप बैठिए तो सही। कोई भी सदस्य बैठे बैठे कमेंट्स न करें इससे हाउस चलाने में दिक्कत आती है। हाउस को चलाना हमारा फर्ज है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, भाहीदो का सम्मान और इस देा के रणबांकुरे, विवाद का या राजनीतिक मतभेद का प्र न ही नहीं हो सकता है। इसलिए जब कर्नल साहब ने यहां पर एक वाजिब सवाल उठाया था तो बड़े खुले दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देा दिया था और बड़ी तफसील से माननीय कर्नल साहब को और आपकी अनुमति से पूरे सदन को यह कहा कि इस मामले में हम बिल्कुल उदार हृदय हैं। न केवल कर्नल साहब बल्कि कोई भी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी को या मंत्री जी को किसी भी वार मैमोरियल के बारे में कोई सुझाव भेज दें तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हम उसको पूरा करेंगे। इस प्रदेा के वित्त मंत्री भी फौजी हैं और वार मैमोरियल के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। जिन्होंने इस देा की सुरक्षा की (गोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, 1857 में
***** (गोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, I am trying to answer, this is not the way, Sir,

Mr Speaker: He is replying your question. Mr Vij, let him reply. (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, जब विज साहब पांच बार खडे हुए मै यील्ड कर गया और मै बैठ गया। मैने उनको बोलने के लिए पूरा दस मिनट का समय दिया ताकि वे अपनी स्पीच दे सके, इसलिए अब उन्हे मेरी बात भी सुननी चाहिए। दूसरी बात सर, विज साहब मेरे बडे काबिल सदस्य है, और मेरे बहुत पुराने दोस्त भी है और हम इकटठे भी रहे है। जब ये सत्ता पक्ष में थे और हम विपक्ष में थे तब भी रहे है। उनको यह मालूम होगा कि कोई आदमी सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में इस सदन में कोई बात नहीं कहनी चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्होने कुमारी भौलता जी की चर्चा की और उनकी घोशणा की चर्चा कीह जा `कि इनकी मौजूदगी में थी। मुझे नहीं लगता कि उस बात की यहां चर्चा की जानी चाहिए। तीसरी बात इन्होने यहां पर कही कि 1857 के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका वार मैमोरियल कब तक बनेगा? इस बारे में कर्नल साहब के प्र न में नहीं पूछा गया था और हैंडी जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है और हो भी नहीं सकती। इसलिए विज साहब अलग से लिख कर भेज दें और मै लिख कर इनको भिजवा दूंगा। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अनिज विज: अध्यक्ष महोदय, (तोर एवं व्यवधान)

Sh. Randeep Singh Surjewala: Sir, he is interrupting me. This is not the way. (तोर एवं व्यवधान)

Mr Speaker: This is not possible. Vij Sahib, I allowed you to speak. Now, let him give his reply.

श्री अनिज विज: अध्यक्ष महोदय, इस मामले मे तो पालिटिक्स नही होनी चाहिए। (तोर एवं व्यवधान)

Sh Randeep Singh Surjewala: This is not a matter of politics. This is a matter of War memorials. you have already made your point. I am trying to say something with the permission of the Chair. (Interruptions) We have to have decorum. decency and mutual respect. सर, जैसा मैने कहा कि हमारे वित्त मंत्री जी स्वयं एक फौजी रहे है और वे दे । की सामाओ की सुरक्षा करके आये है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां तक अपने भाहीदो के लिए, स्वतंत्रता सेनानियो के लिए, फौजियो के लिए कहा है कि पैसे की कोई दिक्कत नही आयेगी। हमारे पास इस समय भी उनके लिए लगभग साढे 6 पौने 7 करोड रुपये का बजट है। अध्यक्ष महोदय, मै आपकी अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से पूरे सदन को यह कहता हूं कि जहां कहीं भी वार मैमोरियल की आव यकता हो, जिस प्रकार के वार मैमोरियल की आव यकता हो, जिस प्रकार का मैटीरियल आप चाहे, जहां मैंटीनैस मे किसी प्रकार की कोताही हो या कोई वि ोश प्रकार की मैंटीनैस आप चाहते है या और कोई साजो

सामान आप चाहते हैं हम भाहीदो का सम्मन कर सके तो इस बारे में हमें सुझाव दे हम उनको अव य पूरा करेंगे।

मुख्यमंत्री (चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडडा): अध्यक्ष महोदय, जो मेरे माननीय सदस्य ने बात कही है उसके बारे में मंत्री जी ने सही जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, लोग समझते हैं कि आजादी की लड़ाई की पहली चिंगारी मेरठ से फूटी थी लेकिन इन्होंने अपनी बात बोलते हुए यह बात कही कि 1857 में आजादी की लड़ाई की पहली चिंगारी अम्बाला से फूटी थी, यह बात सही है और इसका सारी दुनिया को पता है। अध्यक्ष महोदय, 1885 में जसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ उसमें भी अगर कोई हरियाणा से सदस्य था तो वे अम्बाला से लाला जी थे। यह सब हम को मालूम है और इनही चीजों को देखते हुए ही हमने कहा है कि अम्बाला में वार मैमोरियल बनायेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी बात की है, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं खाली एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जो वार मैमोरियल हमारे भिवानी के अंदर है जिसकी चर्चा कर्नल साहब ने की है, क्या हमारे को वहां पर नई जमीन उपलब्ध करवाकर दी जायेगी? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया है कि सबसे ज्यादा वहां से भाहीद हुए हैं और पूरे हरियाणा में से सबसे ज्यादा लोग आर्मी में वहां से ही जाते

है। मंत्री जी क्या हमें वहां पर अलग से जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वहां पर हम वार मैमोरियल बनवा सकें?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य जी की भावना से सहमत हूँ। (विधन) जब आपका ऐसा रवैया है तो आप कैसे भाहीदो का सम्मान करेंगे? (विधन) सर, मैं माननीय सदस्या जी की भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ता हूँ और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस विषय में चाहे किसी भी सम्मानित समस्य का सुझाव हो हम पर पर जरूर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके साथ ही मैं सदन में यह भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस सवाल के आते ही स्पष्ट आदेश दिए थे कि इस बारे में विपक्ष के और निर्दलिय विधायकों के सबके सजै ांज लीजिए। आप हमें इस बारे में लिख कर दीजिए हम जांच करवाकर जो हो सकेगा वह अवश्य करेंगे।

property of Haryana Wakf Board

***102. Shri Aftab Ahmeb:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) the district wise total property of Haryana Wakf Board in the State;

(b) whether whole of the property is in the possession of Wakf Board together with the details of the property in illegal possession;

(c) the steps being taken to vacate property from illegal possessions; and

(d) whether there is any proposal for providing lands for graveyards in the villages and towns in the State of Haryana where Muslim population resides and there is no Wakf Board Property exists?

P.W.D (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):

(a) Sir the details of district wise properties of the Haryana Wakf Board are placed on the table of the House as **Appendix-I**

(b) No Sir, The details are placed on the table of the House as **Appendix-II**

(c) The board has filed suits for possession in the Courts for vacation of Wakf Board Properties from illegal possession. Presently 447 such suits are pending in various courts. Details of the same are appended as **Appendix-III** Besides, there are 189 cases in which the Board has issued notices under Section 54 of the Wakf Act, 1995 against illegal occupants/encroachers and in 24 cases, after conducting proper enquiry, the Chief Executive Officer of the Board has already passed order against the encroachers under Section 54 (3) of the Act and referred to the concerned Sub Divisional Magistrates under Section 55 for execution. For rest of the properties, the action is being taken.

(d) At present there is no policy. However each case will be considered by the Government on receipt of proposal. सर, इसके साथ ही मैं इस सवाल के डी पार्ट में एक लाईन और डालना चाहूंगा। इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने भी हमें आदेश दिए

है कि जहां जहां पर आव यकता है और हमारे पास जमीन है
वहां पर हम ग्रेवयार्ड्ज प्रोवाइड करवायेंगे ।

Sr . No	District	No or Rurla Properti es	No of urban properti es	Total No. of rural & urban Waks Properti es	Area of rural Wakf properties as per Gazette notification			Area of urban Wakf properties as per Gazetter notification			Total area of Wakf Properties		
					Kan al	Mar la	Sq Yd s	Kanal	Ma rila	Sq Yds	Kan al	Marl a	Sq. Yds
1	Ambala	689	386	1075	896 0	3	12	1667	17	9	1062 8	0	21
2	Panchkula	72	29	101	271 3	10	21	89	7	17	2802	17	38
3	Kurukshetra	697	285	982	164 50	15		1492	5	16	1794 3		16

4	Karnal	418	309	727	747 2	9		1376	5		8848	14	
5	Panipat	296	675	971	469 0	12		7014	12	6	1170 5	4	6
6	Sonepat	350	419	769	305 6	5		700	9	9	3756	14	9
7	Faridabad/ Palwal	336	213	549	454 1	8	16	469	1	28	5010	9	44
8	Gurgaon	202	44	246	160 1	5		264	16	12	1866	1	12
9	Mewat	1977	234	2211	321 515	8		1545	8		3369 6	16	
1 0	Rewari	171	82	253	195 4	5		279	20		2234	5	
1	Mohindergar	98	252	350	823	6		14576	6		1539	12	

1	h										9		
1 2	Rohtak	160	135	295	176 7	15		532	14	5	2300	9	5
1 3	Jhajjar	178	108	286	209 6	5		45	16	25	2142	1	25
1 4	Jind	345	80	425	254 9	7		351	2		2900	9	
1 5	Sirsa	362	161	523	896 1	1	11	1339	4	21	1030 0	5	32
1 6	Fatehabad	269	47	316	876 2	19	23	1106	16	9	9869	15	32
1 7	Hissar	397	507	904	538 8	7		1854	3	16	7242	10	16
1 8	Bhiwani	263	123	386	345 0	14		974	13	6	4425	7	6

19	Kaithal	379	162	541	688 6	18	16	1449	17	7	8336	5	23
20	Yamunangar	525	58	583	488 3	17	19	868	8		8752	5	19
		8184	4309	12493	129 153	189	11 8	37989	19 9	186	1671 53	168	30 4

Appendix-II

Sr No	District	No of Wakf Properties in the possession of Wakf Board	No of Properties under enroachment	Grand Total of column No. (3) & (4)
1	Ambala	1019	56	1075
2	Panchkula	79	22	101
3	Yamuna Nagar	580	3	583
4	Kurukshetra	911	71	982
5	Kaithal	530	11	541
6	Hissar	745	159	904
7	Sirsa	460	63	523
8	Fatehabad	296	20	316
9	Bhiwani	312	74	386
10	Karnal	702	25	727
11	Panipat	944	27	971
12	Sonepat	640	129	769
13	Rohtak	218	77	295
14	Jhajjar	189	97	286

15	Gurgan Mewat	2428	29	2457
16	Faridabad Palwal	532	17	549
17	Rewari	249	4	253
18	Mohindergarh Narnaul	324	26	350
19	Jind	422	3	425
		11580	913	12493

*About 450 Acre Wakf lands are under encroachment. Exact area under encroachment is being worked out by demarcation.

Appendix-III

Sr No.	Name of District	Suit for possession filed by the Board
1	Ambala	58
2	Yamunanagar	71
3	Kurukshetra	44
4	Rewari	41
5	Hissar	7

6	Bhiwani	7
7	Sirsa	14
8	Jind	3
9	Tohana	22
10	Kaithal	31
11	Karnal	32
12	Panipat	13
13	Sonepat	59
14	Rohtak & Jhajjar	19
15	Palwal & Faridabad	19
16	Gurgaon Mewat	7
	Total Cases	447

श्री आफताब अहमद: स्पीकर सर, वक्फ बोर्ड प्रापर्टी ऐसी ऐसी प्रापर्टी होती है जिसमे आदमी का अपना इन्ट्रस्ट तो होता नहीं है। आज जमीन के भाव बहुत बढ़ चुके हैं जिसके कारण the department is not able to handle these cases in such a manner. जहां उनके पक्ष को सही रखा जाए। इस कारण से कोर्ट में वक्फ बोर्ड सं संबंधित ज्यादातर केसिज में लीगली हार हो जाती है। क्या सरकार के पास कोई ऐसा मकैनिज्म है जिससे

उसको सुदृढ किया जाए और रिस्पोसिबिलिटी फिक्स की जाए? मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरह के जितने भी केसिज़ है उनको इकट्ठा किया जाए। इस तरह से केसिज़ तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के माध्यम से सोल्व हो सकते हैं। क्योंकि वक्फ एक्ट अब बहुत ही स्ट्रोगली आ चुका है जिससे इललीगल पोजेसिज़ को वैकैट करवाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वक्फ बोर्ड इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाएगा क्योंकि अभी तक तो यह देखा गया है कि कोर्ट में जाकर के वक्फ बोर्ड अपने केस हार जाता है और प्राइवेट पार्टी जीत जाती है। प्राइवेट पार्टी को वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने से काफी फायदा हो जाता है। सर, वक्फ बोर्ड का रवैया इस मामले में बड़ा लचीला होता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को की चिंता के साथ अपने आपको भी जोड़ता हूँ। यह सच है कि बोर्ड की जमीन की बैटर मैनेजमेंट के बारे में आजादी के बाद लगातार प्रॉब्लम उठते रहे हैं और कई बार यह भी देखा गया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज पर इललीगल एनकोचमेंट हो जाती है और उन पर इफैक्टिव कार्यवाही नहीं होती। हमने सबसे पहले हरियाणा वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है उसका फ़ैसल करवाने के लिए आर्डर कर दिए हैं। बहुत सारी नयी प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर आईडेंटिफाईड होने का प्रोसेस इस समय आन है।

जहां तक लीटींगे इन का प्रश्न है हमने उसके लिए बकायदा एक एक जिले की सैपरेट डिटेल्ज अनैक इन बनाकर माननीय सदस्य को दी है। मैं आपकी अनुमती से माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहूंगा कि हम कम से कम वक्फ प्रोपर्टीज की सुरक्षा को लेकर सजग हैं। जहां पर माननीय सदस्य को लगे कि कोई अधिकारी कोताही कर रहा है तो आप बताएं। सैंकडो से भी ज्यादा केसिज है अपैंडिक्स में भी आपने देखा है कि हजार से भी ज्यादा केसिज है इसलिए इनमें से हर केस पर हर समय हम नजर रख सकें, यह संभव नहीं है। फिर भी आपको लगे कि अमुक अधिकारी अमुक प्रोपर्टी के अंदर डिफेंस में गडबड कर रहा है या अमुक प्रोपर्टी में जालसाजी या मिलीभगत से गलत ब्यानी की है तो इसके लिए वक्फ बोर्ड के 1995 के एक्ट में अपील का प्रावधान है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में हम कार्यवाही करेंगे और अपील भी करेंगे। आप इंडीविजुअली इन्सटांस लिखकर दें। अगर माननीय सदन के किसी भी सदस्य के नोटिस में इस बारे में कोई बात आए तो वह उसको लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दें।

श्रीमती सुमिता सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मंत्री जी ने जवाब दिया है और बताया है कि वक्फ बोर्ड की 913 प्रोपर्टीज एनकोच्छ है जबकि 447 प्रोपर्टीज के ही केस सूट फाईल किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से

जानना चाहती हूं कि जो बकाया केसिज रह गए है क्या उन पर भी मंत्री जी कार्यवाही करने जा रहे है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, जैसा सवाल के 'सी' पार्ट के अंदर हमने बताया है कि ये केसिज फाईल हो चुके है और बाकी के केसिज के बारे में भी एक इन लिया जा रहा है। प्रोपर्टी टू प्रोपर्टी अगर आप लिखकर पूछेंगी तो वह किस स्टेज पर है तो मैं बता पाउंगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी कलैक्ट करके आपको भेज दूंगा।

चौधरी मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना भी चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं कि दुनिया के अंदर अगर कोई सच है तो एक ही बात है कि जो दुनिया में आया है वह एक न एक दिन दुनिया से जाएगा और उसे मरना ही है। सर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर वक्फ बोर्ड की करीब 600 वर्ग गज जमीन थी और आज भी है। इस जमीन पर श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बुद्धराम का कब्जा था लेकिन जब वहां के मुसलमानों ने ऐतराज किया और कहा कि वहां पर हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए या मस्जिद बनाने के लिए स्थल नहीं है, जगह नहीं है तो उनके अनुरोध को मानते हुए उसने उस जगह को खाली कर दिया।

श्री अध्यक्ष: आप सीधा प्रश्न करें Don't give the speech.

चौधरी मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, 600 वर्ग गज जमीन हिसार के अंदर है। इसी तरह से यमुनानगर के अंदर ससोला रोड पर एम सी वार्ड नं0 23 में भी जमीन है।

श्री अध्यक्ष: क्या यह पोसीबल है कि हर पा प्रोपर्टी का हवाला दिया जाए? आप रैलेवैन्ट क्वै चन पूछें।

चौधरी मोहम्मद इलियास: सर, मैं जिलेवाईज अर्ज कर रहा हूं। सिरसा जिले के अंदर ऐलनाबाद में भी काफी आबादी देहात में मुसलमानों की रहती है। इसी तरह से माधव सिंधाना भी एक गांव ऐलनाबाद में है जहां पर काफी मुस्लिम रहते हैं। कागजाना गांव के अंदर भी बहुत मुस्लिम रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप तो सारे स्टेट पर आ गए। इन सभी का मंत्री द्वारा रिप्लाइ देना संभव नहीं है इसलिए आप स्पैसिफिक क्वै चन पूछें।

चौधरी मोहम्मद इलियास: सर, जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर कब्रिस्तान के लिए मुसलमानों के पास जगह नहीं है। क्या माननीय मंत्री का ऐसा कोई विचार है कि उनको कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाएगी। स्पीकर सर, क्या मंत्री जी बताएंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर ग्रैवयार्ड के लिए जगह नहीं है क्या वहां के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है कि उनको कब्रिस्तान के लिए जगह दी जाएगी?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद जी ने यह सवाल बकायदा अपने सवाल के डी पार्ट में स्पेसिफिकली पूछा हुआ है और उसका मैं स्पेसिफिक जवाब भी दे चुका हूँ, वह सवाल दोबारा माननीय सदस्य पढ़ ले तो वही जवाब है।

चौधरी आफताब अहमद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ बड़ी बड़ी औद्योगिक नगरियाँ हैं उनमें से फरीदाबाद और पानीपत में हमारी कब्रिस्तान के लिए भूमि की मांग पिछले कई सालों से लंबित है और वहाँ कब्रिस्तान सरकार की जमीन से दिये जाने हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि उसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही करके सरकार कम से कम कब्रिस्तान के लिए तो जमीन दे, यह मेरा भी सरकार से अनुरोध है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: जहाँ तक कब्रिस्तान के लिए जमीन देने की व्यवस्था करने का प्रश्न है जैसा माननीय सदस्य श्री मोहम्मद इलियास जी ने कहा या श्री आफताब अहमद जी ने कहा। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यह डिअैब या विवाद का प्रश्न है ही नहीं हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड एक स्टेच्युरी बॉडी है और कब्रिस्तान के लिए जहाँ भी जमीन है वहाँ हम देने के लिए तैयार हैं। अगर ये लगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है तो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री सुनिश्चित करते हैं कि जहाँ हमारे

माइदनौरिटीज के भाइयो के लिए कब्रिस्तान की आव यकता है उनके लिए नगर पालिका या पंचायत के माध्यम से या किसी भी विभाग की जमीन हो, वहां हम जमीन उपलब्ध करवाने का प्रयास करते है। स्पेसिफिक इंस्टांस लिखकर भेजेंगू तो हम उसकी जांच करवा के सुनिश्चित करेंगे कि उसका हल निकल सके।

Upgradation of Schools

***86 Shri Sher Singh Barshami:** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the total number of Primary, Middle and High schools upgraded in Ladwa Assembly Constituency during the period from 1-4-2005 to date; and

(b) whether there is any proposal under consideration to upgrade the Primary to Middle, Middle to High and High to Secondary Schools during the current and next financial year 2010-2011?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukal Matanhail):

(a) Sir, the total number of schools upgraded in Ladwa Assembly Constituency during the period from 1-4-2005 til date are; Primary Scholl to Middle school- twenty five, Middel school to High scholl-one; and high school to senior secondary school-two;

(b) The upgradation norms for schools are under revision. Further upgradation of schools in Ladwa Assembly

Constituency would be considered after finalization of revised norms.

श्री भोर सिंह बड गामी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब ये स्कूल अपग्रेड किए गए इसके लिए क्या काइटेरिया ऐडॉप्ट किया गया?

श्रीमती गीता भुक्कल मातानहेल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूलज को अपग्रेड करने के जो नार्मर्ज है उसमें प्राइमरी टू मिडल के लिए 150 students and at least 25 students studying in the class 5th for the last two years. 150 students form middle to high. i.e. 6th to 8th and at least 50 students studying in the 8th Class for the last two years and 150 students for high to secondary as per the record of the school. As per the record of the school, the land area for the primary to middle scholl is about one acre, middle to high is about two acrtes and high to senior secondary is two acres. As far as building norms are concerned, for primary to middle school is 8 roons with the condition of one roon per section of the education purpose and the middle to high, 10 rooms from high to senior secondary, 12 rooms are required.

श्री भोर सिंह बड गामी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उस समय जो स्कूल काइटेरिया को फुलफिल करते थे वे सभी अपग्रेड किए जा चुके हैं यदि किए जा चुके हैं तो उनके नाम बताने का कश्ट करें?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि जो स्कूल प्राइमरी से मिडिल अपग्रेड हुए हैं वे 25 हैं। जिसमें पहला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अन्टेडी जिसे 2006 में अपग्रेड किया गया। दूसरा जी एम एस बदरपुर और तीसरा इनके अपने गांव में जी एम एस बडामी है, चौथा जी एम एस बरछपुर स्कूल अपग्रेड किया गया है। इसी प्रकार से जी एम एसए बरौंदी, जी एम एस बरतौली, जी एम एस बहलौरपुर, जी एम एस छपरा, जी एम एस धरौला, जी एम एस हलालपुर, जी एम एस गोविन्दगढ, जी एम एस जैनपुरा, जी एम एस जंघोडा, जी एम एस कालीराव। मिडिल से हाई स्कूल जो अपग्रेड किए गए हैं वे हैं लाडवा, मुनारपुर, सलेमपुर, संभलखोडा, साँती, सुल्तानपुर, सूरा और लोहारा है। इसी प्रकार से हाई से सीनियर सैकेण्डरी स्कूल जो अपग्रेड हुए हैं, वे हैं गवर्नमेंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बाणी और गवर्नमेंट सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बरौंदा।

Smr. Kiran Chaudhary: Mr Speaker: Sir, I would like to request the Hon'ble Minister that in her reply she has said that the up gradation norms of schools are under revision and further up gradation schools will be considered after the finalization of revise norms. As you know well Sir, that education is one of the primary sectors of our Government. That is why, the Government schools attach great deal of priority to it. I would like to ask the Hon'ble Minister when these revise norms are going to be finalized and what is that time bound period? Secondly Sir she has announced that in

every block model schools are going to be put in. So I would also like to ask her through your goodself by what time these model schools will also be started.

Smt Geeta Bhukkal Matanhail: Speaker Sir, I would like to tell the Hon'ble Member as per the revising norms that the school building having more than one storey should provide one ramp and stair case at least six feet width. The reason to revise these norms is because the Right to education Act is going to be implements from 1st April, 2010. So Data regarding the upgradation of schools from the Primary to Middle, Middle to High, High to Senior Secondary schools have been analised during 2009-2010 and after examining it was found that the upgradation of these schools are highly sweeped. The data clearly shows that in some of the places numbers of schools have been upgraded and in some of the pleges number of the schools upgradation were less that's why we have decided that this policy regarding the revision of norms will be finalized by 30th April, 2010. Sir, second query she has asked abou the model schools, As we are considering and cases are pending we will decided it.

Smt. Kiran Chaudhary: Speaker Sir, I just wanted to know from the Hon'ble Minister as the concerned minister has not replied my question.

Mr Speaker: Please take your seat.

श्री भोर सिंह बड ामी: अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्कूल वर्ष 2005 से आज तक अपग्रेडे इन का काईटेरिया फुलफिल करते थे, क्या ये सारे स्कूल

अपग्रेड कर दिए गये है या जो काईटेरिया फुलफिल करते है उनको अपग्रेड किया जाएगा या नही?

श्रीमती गीता भुक्कल: स्पीकर सर, इनकी लाडवा कांस्टीच्यूएंसी के जितने भी स्कूल अपग्रेडे इन के लिए पेंडिंग है उनको नई रिवाईजड पॉलिसी बनने के बाद टेक अप करेंगे। अगर आपकी हमारे पास अपग्रेडे इन की एप्लीके ांज या रिक्वैस्ट आई है और वे भारते पूरी करते है तो उन पर विचार किया जायेगा।

श्री भोर सिंह बड ामी: स्पीकर सर, मै मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस समय अपग्रेडे इन के लिए जो काईटेरिया लागू था और जो स्कूल उस काईटेरिया को पूरा करते थे क्या वे सभी स्कूल अपग्रेड किए जा चुके है या नहीं। यदि काईटेरिया पूरा होने के बाद भी जो स्कूल अपग्रेड नही किए गये है क्या उनको पहले की भारते के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: स्पीकर सर, मै माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इस समय अपग्रेडे इन के लिए जो काईटेरिया को रिवाईज कर रहे है और पिछले as per norms कंसीडर किए है। It depends on the case to case or it is the disrection of the Government for upgradation of the schools we have to take the approval of the F.D and these cases are pending.

श्री भोर सिंह बड ामी: स्पीकर सर, मै मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस समय अपग्रेडे इन के लिए जो

काईटेरिया लागू था और जो स्कूल उस काईटेरिया को पूरा करते थे क्या वे सभी स्कूल अपग्रेड किए जा चुके हैं या नहीं या जो काईटेरिया पूरा करते हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष: बड गामी जी, मंत्री जी ने बताया है कि नई पॉलिसी आ जायेगी उसके बाद इनको कंसीडर किया जायेगा।

श्री अ गोक कुमार अरोडा: स्पीकर सर, लाडवा के अलावा दूसरे जो स्कूल काईटेरिया पूरे करते थे क्या उनको भी अपग्रेड किया जायेगा?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: स्पीकर सर, लाडवा के अलावा हमने टोटल स्कूल जो अपग्रेड किए हैं उनके बारे में मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि पूरे स्टेट में हमने जी स्कूल अपग्रेड किए हैं वे 2006-07 में प्राइमरी से मिडिल 190 स्कूल अपग्रेड किए हैं। इसके अलावा जो स्कूल काईटेरिया पूरा करते हैं उनको भी नई पॉलिसी के तहत डिसाइड करेंगे।

श्री भोर सिंह बड गामी: सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: आपका जवाब आ गया है कि इन नार्मर्ज को रिवाईज करने के बाद जो स्कूल रह गये हैं उनको नयी पॉलिसी के हिसाब से टेक अप किया जायेगा।

श्री भोर सिंह बड गामी: सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: जवाब वही है कि नई पॉलिसी आने के बाद किया जायेगा।

श्री अ गोक कुमार अरोडा: स्पीकर सर, लाडवा के अलावा दूसरे जो स्कूल काईटेरिया पूरे करते थे क्या उनको भी अपग्रेड किया जायेगा?

Mr Speaker: Please take your seat.

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने एक जगह अपने भाषण में यह कहा कि it is the discretion of the Government. मैं मंत्री महोदय जी से क्लेरिफिके इन चाहती हूँ कि क्या डिस्की इन के हिसाब से स्कूलों को अपग्रेड किया जायेगा या सरकार अपनी मर्जी से स्कूलों को अपग्रेड करती है? मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि जो नार्मर्ज पूरा करते हैं क्या उनके हिसाब से उनको अपग्रेड नहीं किया जायेगा?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि upgradation depends on case to case. और जो भी स्कूल हम अपग्रेड करते हैं उसके लिए हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से एप्रूवल लेनी होती है।

Mr Speaker: Now the question hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित
प्रश्नों के लिखित उत्तर

Upgradation of Schools

***108. Shri Rameshwar Dayal:** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the total number of Primary, Middle and High schools upgraded in Bawal Assembly Constituency during the period from 1-4-2005 to date; and

(b) whether there is any proposal to upgrade Primary to Middle, Middle to High and High to Senior Secondary School level during the current and next financial year 2010-2011?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल):

(क) श्रीमान जी, बावल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 1-4-2005 से अब तक स्तरोन्नत किए गये विद्यालयों की कुल संख्या प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय, भून्य, माध्यमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय-1 तथा उच्च विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय-5 है।

(ख) विद्यालयों को स्तरोन्नत करने के मापदण्ड संशोधन हेतु विचाराधीन है। बावल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विद्यालयों को स्तरोन्नत करने के लिए मापदण्ड संशोधित करने उपरांत, विचारा जाएगा।

Punjabi as Second Language

***76. Shri Ashok Kumar Arora:** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the details of the notification declaring Punjabi as the second language of the State:

(b) whether this notification fulfills all the required conditions under the law; and

(c) if the answer to (b) above is in affirmative, then what is the status of Telugu language in the State

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल):

श्रीमान् जी

(क) अधिसूचना की एक प्रति सदन के पटल पर रखी गई है।

(ख) जी हां,

(ग) प्रश्न के (ख) एवं (ग) भाग पारस्परिक असंबंधित हैं।

अधिसूचना

हरियाणा सरकार

शिक्षा एवं भाषा विभाग

दिनांक 28 जनवरी, 2010

संख्या 1/50-2010 प्र 110(2)- हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त भावितयो का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे सूचीबद्ध भासकीय प्रयोजनो मे उपयोग किए जाने के लिए पंजाबी भाशा को द्वितीय भाश के रुप में विनिर्दिष्ट करते है-

(i) राज्य सरकार तथा इसके कार्यालयो द्वारा पंजाबी भाशा मे प्रतिवेदनो को ग्रहण करना तथा

(ii) पंजाबी भाशा तथा पंजाबी साहित्य को बढावा देना।

राजन गुप्ता

वितायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,

शिक्षा एवं भाशा विभाग।

***125. Smt. Sunita Singh:** Will the Environment Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to preserve the environment in the state; if so, the details of scheme?

Finance Minister (Capt. Ajay Singh Yadav): Yes, Sir. The details of the scheme under consideration of the Government are laid on the table of the House.

Details of Schemes

Government of Haryana have been implementing various schemes for the preservation of environment in the State; At present 5 new schemes are under active consideration of the State Government;

1. Introduction of Green Buildings concept.

The Environment Department is considering to issue a notification making adoption of the green building concept compulsory for buildings occupying a prescribed minimum floor area/ plot area. Action has been initiated to prepare a 'Green Manual' for the State.

2. Preparation of Environment Action Plan for the Towns of Faridabad and Panipat.

The central Pollution control Board has conducted a survey of 88 selected industrial areas/ clusters with the help of IIT Delhi and developed a Comprehensive Environment Pollution Index (CEPI). Faridabad comes at Serial No. 18 and Panipat comes at Serial No. 37 in this list of 88 industrial areas/ clusters in descending order of CEPI. The State Government has initiated the preparation of remedial action plan for these two towns to restore their environmental quality,

3. Improved system for the disposal of Bio-Medical Waste.

Since it has been found that present arrangement for Bio-Medical Waste disposal is not satisfactory, the Department of Environment has initiated action to prepare a

more effective plan of action in consultation with the Health Department.

4. Safe disposal of used/fused and disposed of compact fluorescent lamps (CFL),

The department of environment has initiated action to prepare a plan for collection of disposal of used/fused and disposed of Compact Fluorescent Lamps (CFL) with the help of municipal Committees.

5. Restructuring of Haryana State Pollution Control Board.

It is felt that with the increased emphasis on environment, there is need for strengthening of the Haryana State Pollution Control Board. The Board is preparing a restructuring plan accordingly.

Crime Against Women

***83 Shri Ajay Singh Chautala:** Will the Chief minister be pleased to state-

(a) the yearwise total number of cases registered relating to Crime against women, for the period 2001 to 2009; and

(b) the yearwise number of cases registered, for the crime of female foeticide during the period 2001 to 2009?

मुख्यमंत्री (श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा): वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

बिन्दु (क)

महिलाओ के विरुद्ध अपराध से संबंधित दर्ज मुकदमे

अपराध का भीर्ष	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
महिलाओ के विरुद्ध अपराध	3391	4383	4132	4160	4107	4660	4756	5095	5415

बिन्दु (ख)

कन्या भूण हत्या के दर्ज मुकदमे

अपराध का भीर्ष	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
कन्या भूण हत्या अपराध	26	25	29	36	41	47	30	45	44

To Regularise Jhuggi/Basties

***92. Shri Krishan Pal Gujjar:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize Jhuggi/Basties of Faridabad; if so, the time by which these Jhuggi/Basties are likely to be regularized; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to start development works in the above said Jhuggi/Basties?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह):

(क) नगर निगम, फरीदाबाद, फरीदाबाद में झुग्गी बासाये को पुनर्वासित/पुनर्स्थापित करने के लिए योजनाएं तैयार करता आ रहा है।

(ख) उपरोक्त 'क' के दुर्दृष्टीगत झुग्गी/बस्तियों के विकास कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Facility to Post-mortem

***120 Shri Kali Ram:** Will the Health Minister be pleased to state-

whether there is a provision of any room for post-mortem in Government Hospital. Safidon, if so, the reason for not doing post-mortem in the above said hospital?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल): हां श्रीमान जी, सरकारी अस्पताल, सफीदो में पोस्टमार्टम के लिए एक कमरा उपलब्ध है। अस्पताल में अब पोस्टमार्टम कार्य करने की व्यवस्था कर ली गई है।

Posting of Principal in I.T.I Kalka at Bitna

***150. Shri Pardeep Chaudhry:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the post of Principal in ITI kalka at Bitna is lying vacant; if so, the time by which this post is likely to be filled up;

(b) whether the posts of Group instructor and instructors in ITI Kalka are lying vacant; if so, the time by which these posts are likely to be filled up; and

(c) whether the Heavy Vehicle Motor Mechanic course is being run in ITI Kalka; if so, whether any practical training is also being imparted to the students of this course?

मुख्यमंत्री (श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) हां, श्रीमान् जी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालका एट बिटना में प्रधानाचार्य का पद 1.8.2009 से रिक्त है तथापि आदेश दिनांक 8.3.2010 अनुसार श्री राम कुमार की नियुक्ति प्रधानाचार्य आई० टी० आई० कालका के पद पर कर दी गई है।

(ख) हां, श्रीमान् जी, वर्ग अनुदेशक के 3 पद तथा व्यवसाय अनुदेशक के 30 पदों में से 2 पद वर्ग अनुदेशक तथा 16 पद व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त हैं। इन पदों को भीघ्न ही भना जाना सम्भावित है।

(ग) मैकेनिक रिपेयर एवं मेंटेनेंस आफ़ हैवी व्हीकल व्यवसाय औद्योगिक प्रििक्षण संस्थान कालका में चल रहा है। इस व्यवसाय के छात्रों को अधिकतर व्यावसायिक प्रििक्षण संस्थान में ही दिया जा रहा है। व्यावसायिक प्रििक्षण का प्रबंध हरियाणा परिवहन कार्य ाला चण्डीगढ में भी किया गया है, जब तक संस्थान में इस व्यवसाय की पूर्ण म िनरी उपलब्ध नहीं हो जाती।

Construction of New Road

***145. Shri Charanjeet Singh:** Will the P.W.D (B&R) Minister be pleased to state the names of new roads constructed in Kalanwali constituency during the period from 2005 to 2009 together with the total amount incurred thereon?

लोक निर्माण (भवन तथा सडके) मंत्री, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: कालांवाली निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2005-2009 के दौरान जिन नई सडको का निर्माण हुआ उनके नाम निम्नलिखित हैं:-

क्र० संख्या	सडक का नाम
1	तारुआना में तारुआना कालांवाली रोडी लिंक सडक
2	लोक निर्माण विभाग सडक से गुरुद्वारा बडागुडा लिंक सडक

3	थिराज से मलहारी पुल तक लिंक सडक
4	बडागुडा से धबन भंगू लिंक सडक
5	भीमा से रोहन तक लिंक सडक
6	गदरान से चकेरियो तक लिंक सडक
7	बीरुवाला गुडडा से सुबाखेडा तक लिंक सडक
8	दादू से तखतमल तक लिंक सडक
9	दादू से कमल तक लिंक सडक
10	तारुआना से कलूआना छोटे पूल तक लिंक सडक
11	आनंदगढ से रघुआना
12	पक्का से कोरिआला पंजाब सीमा तक लिंक सडक
13	रघुआना से साहुबाला 1 तक लिंक सडक
14	रोडी मे अनाज मण्डी की सडको को जोडना
15	नरेल खेडा से भावदीप तक लिंक सडक
16	फरवेन कलां से दरवी तक लिंक सडक
17	मुख्य सडक से वाटर वर्क नगोकी तक लिंक सडक

18	छतरगढ पटटी झोम्पडा
----	--------------------

इन सडको के निर्माण पर 314.92 लाख रुपये की कुल राशि खर्च हुई।

Occupation of the leasehold Houses and Plots

***149. Smt Kavita Jain:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give ownership by making registries in favour of these occupants of the plots of shops and houses given to them on lease by the Municipal Council, Sonapat; and

(b) if so, the time by which the registries are likely to be started together with the rate at which the said registries will be executed; and if not, the reasons thereof?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह):

(क) यदि पटटेदारो को अलाट भूमि/भवन और दुकानो का मासिक किराया 500 रु से कम है और वह सम्पत्ति लंबे समय से उनके कब्जे में है तो सरकार की इस बारे में नीति है।

(ख) नगरपरिशद सोनीपत ने इस प्रकार की सम्पत्तियो के सर्वेक्षण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। इसे नीति के अनुसार विचारा जायेगा।

To Segregate the load of Domestic Agricultural Sectors

***5 Shri Ram Pal Majra:** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any scheme to segregate the load of domestic sector and agricultural sector for the distribution of electricity in the State; if so, the time by which the aforesaid scheme is likely to be implemented together with the circle wise details thereof?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह): हां श्रीमान जी, राज्य मे ग्रामीण घरेलू तथा कृषि पावर लोड को अलग करने की एक योजना लागू की गई है। विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

सर्कलानुसार नए फीडरो का विवरण निम्न प्रकार है:-

सर्कल का नाम	स्थापति किए जाने वाले फीडरो की संख्या	अलग करने का कार्य पूरा होने वाले फीडरो की संख्या	फीडरो की संख्या जिन पर कार्य प्रगति है	पूरा होने की सम्भावित तिथि
उ० ह० बि० वि० नि०				
अम्बाला	63	63		

यमुनानगर	84	84		
कुरुक्षेत्र	87	87		
कैथल	69	69		
करनाल	118	112	6	31.03.2010
पानीपत	46	43	3	15.04.2010
सोनीपत	73	67	6	31.03.2010
जींद	33	33		
रोहतक	45	45		
योग	691	676	15	
द० ह० बि० वि० नि०				
फरीदाबाद	55	55		
गुडगांव	66	37	29	30.04.2010
नारनौल	128	128		
भिवानी	72	60	12	31.03.2010
हिसार	131	122	9	31.03.2010

सिरसा	83	83		
योग	535	485	50	

Shifting of Indian Oil Depot

***4. Shri Anil Vij:** Will the Food & Supplies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift Indian Oil depots out of their town which are situated on G.T. Road, Ambala Cantt. in thickly populated locality; and

(b) if so, the time by which aforesaid depots are likely to be shifted?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह):

(क) हां श्रीमान जीं

(ख) समय अवधि बता पाना सम्भव नहीं है।

Level of New Urlana Minor

***21 Shri Krishan Lal Panwar:** Will the Irrigation Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that water does not reach upto village Kurana situated on the tail of New Urlana Minor, District Panipat emanating from the Bitana canal; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to level the new Urlana

minor; if so, the time by which the said minor is likely to be leveled?

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव):

(क) नहीं श्रीमान जी, जब बुटाना ब्रांच नहर में पर्याप्त पानी उपलब्ध होता है तब जिला पानीपत के गांव कुराना मे जोकि नई उरलाना माइनर के अंतिम छोर पर स्थित है, तक पानी नहीं पहुंचता है।

(ख) नहीं श्रीमान जी।

Illegal Buses and Vehicles

***50 Smt. Kiran Choudhary:** Will the Transport Minister be pleased to state

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to check plying of illegal buses and vehicles in the state; and

(b) if so, the action taken against the defaulters?

परिवहन मंत्री (श्री औम प्रकाश जैन):

(क) मोटर यान अधिनियम, 1988 और नियम के अन्तर्गत अवैध बसों और वाहनों के संचालन निरीक्षण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने पहले ही कार्य आरम्भ किया हुआ है। इसके लिए किसी तरह के अन्य प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

(ख) दोशियो के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2009-10 (अप्रैल 2009 से जनवरी 2010) के दौरान विभिन्न प्रकार के 29164 वाहनो का चालान किया और इन वाहनो से समझौता/ जुर्माना में 33.90 करोड रुपये वसूल किए।

Land tyransferred by HSIIDC to Reliance

***84 Sh Ajay Singh Chautala:** Will the Industries Minister be pleased to state-

(a) how much land has been transferred by HSIIDC to Reliance Haryana SEZ and how much land has been purchased by Reliance for setting up the said SEZ/SEZs in Haryana.

(b) at what cost did the HSIIDC transfer the acquired land to Reliance for setting up the SEZ and at what price did Reliance buy the land for the said purpose directly from the farmers; and

(c) how much employment was required to be generated in the sanctioned SEZs and how much employment has actually been provided particularly for those belonging to Haryana?

बिजली मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह): श्रीमान जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा जाता है।

(क) मैं रिलायंस हरियाणा वि शेष आर्थिक जोन को हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (एच एस आई आई डी सी) द्वारा 1363.68 एकड भूमि स्थानांतरिक की गई है।

मै0 रिलायंस हरियाणा वि ेश आर्थिक जोन ने भी 8202 एकड भूमि सीधी खरीदी है। जिसमे से 1201 एकड भूमि जिला गुडगांव तथा 7001 एकड भूमि झज्जर जिला में हे।

(ख) हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम ने अधिग्रहित भूमि रिलायंस हरियाणा एस ई जैड लिमिटेड को वि ेश आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए 28.90 लाख रु प्रति एकड की दर से स्थानांतरित की है। एकमूस्त रािा के अतिरिक्त हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (एच एस आई आई डी सी) को इस परियोजना में 10 प्रति ात मैत्री इक्यूटी मिलेगी। भू मालिको को तीस हजार रु प्रति एकड प्रति वर्ष की दर से सुविधा (Annuity) दी जाएगी और अब तक 8.38 करोड रु भू मालिको को अदा किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त रिलायंस हरियाणा वि ेश आर्थिक जोन ने भी भू मालिको / किसानो से सीधे तौर पर 22.00 लाख रुपये प्रति एकड की दर से भूमि खरीदी है।

(ग) प्रोजैक्ट रिपोर्ट के अनुसार जब वि ेश आर्थिक जोन पूर्णतः कार्यान्वित होगा, उसके लगभग 4 लाख व्यक्तियो को रोजगार मिलेगा (2 लाख प्रत्यक्ष तथा 2 लाख अप्रत्यक्ष) इस परियोजना को चरणो मे विकसित किया जायेगा। कम्पनी ने अभी परियोजना की प्लानिंग तथा अनुमोदन हेतु 460 व्यक्तियो को रोजगार दिया हुआ है, इनमे से 316 व्यक्ति हरियाणा से संबंध रखते है।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under rule, 30.

PWD (B&R) Minister Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, i beg to move

“That Rule 30 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, 11th March, 2010.”

Mr Speaker: Motion moved-

“That Rule 30 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, 11th March, 2010.”

Mr Speaker: Question is-

“That Rule 30 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, 11th March, 2010.”

The motion was carried.

विभिन्न विशयो का उठाया जाना/वाक आउट

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैने एक इम्पोर्टेंट नॉन आफिियल रैजोल्यूशन दिया है कि लखवार, किसान और

रेणुका डैम बनाने के लिए केन्द्र सरकार को हाउस की तरफ से रिकमंडे इंज भेजी जानी चाहिए क्योंकि प्रदेश में पानी की भाँटेज है। अध्यक्ष महोदय, ये न तो एस वाई एल केनाल के केस को सुप्रीम कोर्ट में फालो अप कर रहे हैं, और न ही प्रैजिडेंट रैफ्रेंस के लिए कभी कोर्ट में गए। (गोर एवं व्यवधान) हांसी बुटाना ब्रांच नई नहर इन्होंने बिना मंजूरी के ही बना दी। (गोर एवं व्यवधान)

Mr Speaker: Majra Sahib, please listen. Please take your seat.

मुख्यमंत्री (श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, ये हाउस को और हरियाणा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कल सभी मैम्बरज बोल लेंगे इसलिए नॉन ओफिशियल डे को नॉन ओफिशियल डे ही रखें। (गोर एवं व्यवधान)

Mr Speaker: Majra Sahab, Please take your seat.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से केवल एक बात कहना चाहता हूँ। औसत प्रकार का चौटाला जी यहां मौजूदा है। ये मुख्यमंत्री हैं और रामपाल माजरा जी भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। ये आज नॉन ओफिशियल डे की दुहाई दे रहे हैं जबकि इन्होंने अपने 5 साल

के कार्यकाल में एक बार भी नॉन आफिं टायल डे नहीं करवाया। इस प्रकार का इनका व्यवहार रहा है। (गोर एवं व्यवधान) हम तो हमें गोर आफिं टायल डे करवाते रहे हैं। इस सरकार के पिछले 5 सालों में हम लगातार नॉन आफिं टायल डे करवाते रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अ गोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, उस समय इन्होंने कभी कोई रैजोल्यूशन नहीं दिया था। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इस बार कोई रैजोल्यूशन नहीं था इसलिए हमने नॉन आफिं टायल डे को आफिं टायल डे में कंवर्ट कर दिया है। अमर प्रकाश चौटाला जी बी ए सी के मैम्बर हैं और उनकी सहमति से ही नॉन आफिं टायल डे को आफिं टायल डे में कंवर्ट किया गया था। ये लोग इस बारे में अपने नेता से बात कर सकते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, *****
(गोर एवं व्यवधान)

Mr Speaker: Majra Sahib, would you please sit down? (Interruptions)

श्री भोर सिंह बड गामी: अध्यक्ष महोदय, आज बजट पे गोर होना है। हरियाणा प्रदेश का बजट सै गोर चल रहा है। बजट की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। प्रदेश की जनता की

निगाहे बजट पर होती है कि हरियाणा सरकार अपना क्या बजट पे 1 करेगी? बजट पर किसान की भी नजर होती है और व्यापारी की भी नजर होती है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: वित्त मंत्री जी अभी बजट पे 1 किया ही नहीं इससे पहले ये बीच में कैसे इंटरवीन कर सकते हैं? (गोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये पहली बार चुनकर आए हैं, इनकी कोई क्लास लगाएं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री भोर सिंह बडामी: अध्यक्ष महोदय, बजट पर कर्मचारियों की नजर होती है। सह अपना नफा नुकसान देखते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

Mr Speaker: This is not relevant. (Interruptions)

Sh. Randeep Singh Surjewala: Sir, how he can intervene like this. (Interruptions) The Finance Minister is waiting for presenting the Budget and in between he is making running commentary. He should not be permitted to behave like this. (Interruptions)

श्री अ गोक कुमार अरोडा: अध्यक्ष महोदय, बजट जो पहले ही लीक हो गया। (गोर एवं व्यवधान) बजट की गोपनीयता तो रही ही नहीं (गोर एवं व्यवधान)

श्री औम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमारी बात नहीं सुनी जा रही इसलिए एज ए प्रोटैस्ट हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन मे उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल और रिपब्लिकन अकाली दल के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, हमारे वकर्स पर 28 फरवरी 2010 को चण्डीगढ़ पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने के बारे में मैंने कालिंग अटेंशन माँगा था। उसका क्या फेट है? (गौर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विज साहब, प्लीज आप बैठे। (गौर एवं व्यवधान) आज वित्त मंत्री जी बजट रखेंगे और बजट के दिन प्रेस काल के अलावा और बिजनेस नहीं होता। (गौर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, हमारी बात नहीं सुनी जा रही इसलिए एज ए प्रोटैस्ट हम भी सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन मे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

वर्ष 2010-2011 के लिए बजट अनुमोदन प्रस्तुत करना

Mr Speaker: Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Budget Estimates for the year 2010-2011.

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं बजट पे आकर मैं तहे दिन से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि यह बजट मैंने आपकी अपेक्षाओं और हरियाणा के हितों को सर्वोपरि रख कर तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिशें आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। जैसे किसी भायर ने कहा है कि

जो तूने आज सोचा है

वही मैंने भी सोचा है

तेरी आखों का एक ख्वाब

इन आखों से मैंने भी देखा है।

Hon'ble Speaker Sir,

I rise with the sense of pride and humility to present the Budget Estimates for the financial year 2010-2011 before this august House. I stand with a sense of pride because our Government in its previous tenure performed exceptionally well on all fronts of development. The people of Haryana have appreciated this performance and in a historic verdict, have returned our Government to power for another tenure. I stand in all humility in view of the tremendous faith our citizens have reposed in our Government. Sir, through this august House I wish to assure the people of Haryana that this Government will totally dedicate itself to working for their welfare.

2. The world witnessed a severe economic recession in the previous year. which bordered on the worst economic depression the world has seen in recent past. Many financial and corporate bodies were driven to the brink of bankruptcy and millions of people were rendered jobless and homeless, Major economics were seriously threatened. Our country, if fact, is amongst the few nations less affected by the economic slow down. The credit for this goes to the robustness and self dependence of the Indian Economy. as well as the strategic reforms and correst measures taken in the recent past by the Governement of India, under the competent leadership of Dr. Manmohan Singh. There is no doubt, Hon'ble Speaker Sir, that the world will take a long time to recover fully from this crisis. However, clear signs have now appeared that for our National and State economics, the worst may be over and the proverbial light is visible at the end of the tunnel. I am optimistic that the concerted efforts of our Government, with the support of ths private sector and the people of Haryana. will be able to bring Haryana back on the path of growth and prosperity.

3. Sir, in times of severe economic recession, Government spending is one of the major tools for arresting downturn. In the wake of the recession, the revenue receipts of the State were adversely affected. There was a significant decline in the growth rate of State tax revenues and collections under Stamp & Registration and Urban Development. Moreover, for the welfare of its employees, the State has fully implemented the pay revision package, which has cast a burden of over Rs. 4000 crore during the current year. Despite these strains, the Government has not shied away from its responsibilities, and has actually increased the

outlay for Annual Plan 2009-2010 from the budgeted figure of Rs. 10000 crore to Rs. 10400 crore in the Revised Estimates, which is 46-31% higher than the actual plan expenditure in 2008-09. This reflects the deep commitment of our Government to fight the economic recession with all measures at its disposal and to maintain the pace of development in the State.

4. Our National and State economics are now showing signs of resurgence from the depression. Our country is poised to achieve a growth of over 7% in its G.D.P in the current year. In fact, the performance of the UPA Government at the Centre, under the visionary guidance of Chairperson Smt Sonia Gandhi, is so remarkable that in the World Economic Forum, recently held in Switzerland, experts projected that India is like to emerge as the fastest growing economy in the world in 4 to 5 years. The State tax revenue receipts are also improving and the VAT collections during the latter half of this financial year reflects very positive trends. Therefore, Speaker Sir, I am optimistic that Haryana is now emerging from the clutches of economic recession and our Government shall strive hard to take it further on the path of growth.

STATE ECONOMY

5. During the financial year 2008-09, the State economy witnessed a very healthy growth of 18.4% in the **Gross State Domestic Product** (GSDP) over the previous year at current prices. At constant prices, with base year 1999-2000, the growth in GSDP in 2008-09 is 7.9%. The Primary sector contribution to GSDP stands at 19.8% in 2008-09 and

51.4%. The sectoral analysis reveals that, at constant (1999-2000) prices, the contribution of the Primary Sector to Gross State Domestic Product has registered an increase of 3.5 percent, while that of the Secondary Sector increased by 5.4 percent, and that of the Tertiary Sector recorded a growth of 11.2 percent. The declining share of the primary Sector in GSDP and the increasing share of the Secondary as well as Tertiary Sector indicate a maturing of our economy, and its growth in the right direction. As per advance estimates, the GSDP at current prices for 2009-2010 is likely to grow by 14.7% while at constant (1999-2000) prices, the expected growth is 8.1%.

6. The per capita income of Haryana at current prices increased by 16.8% from Rs. 59008 in 2007-08 to Rs. 68914 in 2008-09. At constant prices, it increased by 6.2% from Rs. 39462 in 2007-08 to Rs. 41896 in 2008-09. During the current year, it is likely to grow further by 13% to Rs. 77878 at current prices, and by 6.2% to Rs. 44493 at constant prices. Haryana has the second highest per capita income amongst the States in India, being second only to Goa.

7. It is a matter of great pride for all Haryana is that Haryana has the highest per capita income among the major States in the country. However, our state has suffered a disadvantage on this account in the report of the Thirteenth Finance Commission (TFC). The TFC has used the per capita income of Haryana as the yardstick to measure a criteria called “**Fiscal Capacity Distance**” in its formula for horizontal distribution of central taxes amongst States. this criteria has been assigned the maximum weight of 47.5% whiel

the other criteria namely, **Population area** and **Fiscal discipline** have been assigned weights of 25%, 10% and 17.5% respectively. Thus, due to this unique position, the share of Haryana in shareable pool of Central taxes has marginally come down from 1.075% to 1.048%. However, the total devolutions to Haryana under the 13th Finance Commission's recommendations are Rs. 19470.30 crore as compared to devolutions of Rs. 8040.44 recommendations are Finance Commission period. I congratulate the Union Government on increasing the size of the divisible pool of the Central taxes from 30.5% to 32%.

NEW INITIATIVES

8. It is estimated that, in order to sustain a growth of 8 to 9 percent in the national economy, an investment of nearly Rs. 23 laksh crore is required on improvement of infrastructure during the 11th Five year plan. Investments of a similar order of magnitude would naturally be required in the State. You would agree, Sir, that this magnitude of investment is not feasible from the budgetary sources of the Governemnt alone. Our Government is, therefore keen on involving the Voluntary, Non Government and Private sectors in our development process. We believe the participatory mode of development to be the best for our State and our society, and this is reflected sharply in our new initiatives which I will now outline before this august House.

Policy for Non Government Organizations and Voluntary Sector

9. Our Government recognized that the Voluntary and NGO sectors can work as effective instruments of inclusive development, by helping with proper identification of beneficiaries. reduction of delivery costs, flexibility and simplicity of approach and greated community participation in formulation of new schemes. As a logical extension of Decentralized Planning, we propose to formulate a policy for engaging the Voluntary and NGO sectors as development partners for the State. The policy would provide a framework for assisting such organizations through three instruments of partnership, namely, **Consultation-** through a formal process at the District and State level; **Stratefic Collaboration-** to tackle complex interventions; and **Project Funding.** The project administration would be on the decentralized pattern recommended by the Planning Commission in the National Policy on the Voluntary Sector, and Mother NGO's will be involved to select, train,. fund and concurrently monitor field projects being implemented by field NGO's on behalf opf the Administrative Departments. This would bring in greater responsibility transparency and accountability to our Social sector projects.

Policy for Public Private Partnership Projects

10. In the complex current economic scenario, adequate development of social and physical ingrastructure, which are pre requisites for sustainable economic growth, can only come from pooling of all available resources- from Government, Non Government as well as private sectors. Therefore, the Public Private Partnership (PPP) mode of development assumes great significance. We propose to

formulate a comprehensive policy on PPP projects in order to create an enabling environment in the State for facilitating private sector participation in improvement of the physical and social infrastructure. We intend to extend the PPP approach even to niche areas such as providing tertiary level health care at affordable cost to our population.

Haryana Infrastructure Development Board

11. Providing a framework for fast track implementation of the PPP projects is necessary to fully reap the benefits of the major investments we hope to initiate through the policy on PPP. We propose to do so by setting up **Haryana Infrastructure Development Board**, which would act as a nodal agency for conceptualization, financing, implementation, maintenance and operation of PPP projects in the State and also as a special purpose vehicle to take up major infrastructure projects funded out of State resources and other levies and charges.

East-West and North South Expressway Corridors

12. Sir, our Government has the grand vision to spread the benefits of economic development to the remotest corners of Haryana. We propose to open up the hinterland by providing easy access by building an East West and a North South expressway corridor through the State. The project, likely to cost around Rs. 2000 crore, will be in the PPP mode with a mixed model of BOT (Toll) and BOT (Annuity). The interior areas along th corridors will open up for industrial, economical, estate development and allied activities, thereby creating enormous opportunities for growth and employment.

Haryana Metro

13. The proximity to Delhi is a unique advantage for Haryana and our State territories constitute a large part of the National Capital Region. To fully exploit this advantage, we intend to set up Metro rail links connecting our boarding cities with Delhi. The 7.05 Km long Gurgaon Delhi Metro link is near completion. We propose to extend this to manesar and also provide a high speed link to the Indira Gandhi International airport. Sikanderpur station is going to be connected via a 100% private Metro link to NH 8 by M/s Rapid Metro Rail, Gurgaon Ltd. Delhi metro is to be extended to Faridabad through a 13.87 km link. The project for linking Bahadurgarh to the Mundka border of Delhi is under process. At present, the various metro projects of Haryana are being implemented by the Delhi Metro Rail Corporation, which is a joint venture company of the Government of Delhi and the Government of India. For speedy and efficient implementation of our Metro projects, we propose to set up a joint venture company with the Government of Haryana holding a majority equity share, as has been done by the States of Karnataka and Tamil Nadu.

Rajiv Gandhi Urban Development Mission, Haryana

14. The population of our cities has been steadily increasing, and there is a growing need for holistic development of the urban areas with focus on improvement in infrastructure, efficient service delivery mechanisms, community participation and transparency. The Government proposes to launch **Rajiv Gandhi Urban Development**

Mission, Haryana (RGUDMH), a state wide urban infrastructure development program, in all cities of the State excluding those covered under **Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission**. RGUDMH will be funded from the budgetary allocations as well as contributions from the Fund for development of major infrastructure projects, and will catalyze further investments under PPP mode. I with a sum of Rs. 500 crore for RGUDMH over the next five year, beginning with a sum of Rs. 500 crore during 2010-11. **Rajiv Awas Yojna** of the Government of India; water supply, storm water drainage and sewerage, integrated solid waste management, and other civic amenities. For 2010-11 RGUDMH will broadly spend Rs. 200 crore on projects for water supply and sanitation. Rs. 100 crore on affordable housing projects, and the remaining funds will be used for special purpose infrastructure development projects in small and medium towns. the nodal agency for implementation of Rajiv Gandhi Urban Development Mission, Haryana shall be Haryana Urban Infrastructure Development Board which would now be headed by the Hon'ble Minister. There will be a State Level Committee headed by the Chief Secretary for identifying and recommending the projects and overseeing their execution.

Mahatma Gandhi Swavlambhan Pension Scheme

15. Our Government firmly believes that every human being has the right to a dignified old age and has significantly enhanced the old age pension. However, a large section of our working rural and urban population, particularly those working in the informal or unorganized sectors, is vulnerable to old age poverty. We propose to initiate

Mahatma Gandhi Swavlamban Pension Scheme for the members of milk cooperatives and cane growers' cooperatives, wherein each member will contribute Rs. 200 per month, the Society/Federation/State Government will; co-contribute Rs. 100 per month, and the Government of India will co contribute Rs. 1000 per annum. The contributions will go to a fund managed professionally as per the guidelines of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. The fund will provide the worker with a retirement pension to support him in his old age.

Economic Stimulus Package

16. Hon'ble Member would recall that my predecessor had introduced an Economic Stimulus Package in the last budget to help fight the recessionary trends of the economy. Various works have been initiated under this package, such as upgradation of district hospitals, setting up the new medical colleges, improvement of water supply and sanitation facilities in urban areas, setting up of special care institutions for the disadvantaged sections of the society, restoration of water courses, housing for the industrial workers and construction of office and residential buildings for the new district of Mewat and Palwal. Rs. 332.56 crore have been released under the stimulus package so far, and I have made an allocation of Rs. 713.79 crore for the works under the Stimulus package for 2010-11.

17. Sir, before I take up sector wise allocations, let me just highlight a few facts which will put the efforts of our Government in the right perspective. the total plan expenditure during the five years from 2000 to 2005 was only

Rs. 9235.41 crore, whereas the plan expenditure for just the current year is going to cross Rs. 10,400 crore, In the last five years, our Government spending on the State Plan was 230.13% higher than that of the previous regime. The average annual plan outlay growth rate during 2005-2010 is 37.83% per year, compared to just 4.8% during 2001-2005. This has been made possible by the strong commitment of our Government to development of the State.

POWER

18. Universal availability of quality power is critical for the economic development of the State, as well as for the comfort of its citizens. Our Government has accorded the highest priority to this sector and we are committed not only to adding adequate generation capacity to achieve the target of making Haryana a power surplus State, but also to upgrading our transmission and distribution systems for maximum efficiency and reliability. Due to the efforts of our Government. Hon'ble Speaker Sir, the average power availability per day in the State, which was only 578 lakh units in 2004-05 has gone up to 907 lakh units in the current year.

19. Tremendous progress is being made in enhancing the power generation capacity of the State, I would like to inform the Hon'ble Members that, in the period from 1999 to 2005, only 704.4 MW was added to the own generation capacity of Haryana, whereas during the first tenure of our Government from 2005 to 2010 we have already added 1117.8 MW. The first 600 MW unit of the 1200 MW **Rajiv Gandhi Thermal Power Project** at khedar, Hisar has already been

synchronized on 29.12.2009 and the second unit will be ready for commissioning in April, 2010, This will be followed by the first 500 MW unit of **Indira Gandhi Super Thermal Power Station** at Jhajjar, in July, 2010 and subsequently the second & third 500 MW Units in December, 2010 and February, 2011 respectively. The first 660 MW unit of **Mahatma Gandhi Super Thermal Power project** at Jhajjar is targeted to be commissioned during December, 2011 and another 660 MW Unit-II will start generating power by May, 2012. For the 2800 MW **Nuclear Power Plan** to be set up at village Gorakhpur in district Fatehabad, pre-project work has been started by the Nuclear Power Corporation of India limited for setting up two Units of 700 MW each in the first phase. Sir, you would agree that we are well on our way to double the availability of power in the State by 2011-12.

20. For up gradation of the transmission network in the State, Rs. 3365.8 crore are being spent to add 25 substations of 66 KV and above in 2009-2010, and 72 substations in 2010-11. The first 400 KV substation of the State has been set up at Kirori. We plan to augment our transformation capacity by 5000 MW during the 11th Plan.

21. Our effort, Sir is to provide quality power to all citizens. Segregation of the rural domestic and agricultural loads and introduction of High Voltage Distribution System are important steps to improve the quality and efficiency of power supply in the rural areas. Under the **Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojna**, 91347 connections have so far been released to families below poverty line (BPL) this year.

22. I am allocating Rs. 4642.71 crore for this sector during 2010-11 which is 20.06% higher than the allocation for the current year. This includes Rs. 1670.70 crore on Plan side and Rs. 2972.04 crore on Non plan side.

WATER SUPPLY AND SANITATION

23. Sir, a milestone was achieved in 1992, when drinking water supply facilities were extended to all the villages in the State, However, the approved norm of 40 liters per capita per day (lpcd) could not be achieved in some villages. A comprehensive survey in December, 2004 identified 1971 such villages. Our Government has accorded high priority to augmentation of water supply in these deficient villages, and I am proud to augmentation of water supply in these villages would stand augmented as per approved norm by 31st March, 2010. In addition, augmentation of the water supply is being carried out in 950 villages under various schemes during this year.

24. The **Rajiv Gandhi Drinking Water Supply Augmentation Project** in Mewat will be completed by March, 31 2010, covering 503 villages at a cost of Rs. 205.91 crore. Further augmentation of water supply from 55 lpcd to 70 lpcd in all these villages, with an outlay of Rs. 94.58 crore, will commence in 2010-11. Under the **Indira Gandhi Drinking Water Scheme**, private water connections have been provided to 7.83 lakh Scheduled Caste households.

25. Adequate attention is also being given to improving the water supply and sanitation facilities in the urban areas. Our Government has waived the sewer

connection charges for a period of one year from November, 2009 in order to encourage the improvement of sanitary conditions in towns. Second water works based on canal water filtration have been commissioned in Rohtak and Dadri, and sewage treatment plants have been commissioned in Kaithal and Jind, while those in Rohtak, Hodal and Narwana are near completion.

26. In the National Capital Region water supply projects for 10 towns and sewage system projects for 8 towns are under implementation with support from the NCR Planning Board. This year, sewage system projects in Sonapat and Gohana, and a water supply project in Sonapat have been approved.

27. Under the Economic Stimulus Package, 15 towns have been selected. namely, Ambala City, Bhiwani, Charkhi Dadri, Fatehabad, Hansi, Jullana, Kalayat, Assandh, Kaithal, Mahendergarh, Narnaul, Sirsa, Ellenabad, Tohana and Uchana for 100% coverage of water supply and sewerage facilities. Phase-I of the project amounting to Rs. 955.71 crore, has recently been approved by the Government.

28. I am allocating Rs. 1297.69 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 669.48 crore on Plan side and Rs. 628.21 crore on Non-Plan side.

ROAD NETWORK AND PUBLIC WORKS

29. Sir, our Government is committed to improving the road network in the State. up to 31.1.2010 during the current financial year, 3903 km length of roads has been improved at a cost of Rs. 1476 crore under various schemes

and projects. A length of approximately 4100 km will be widened/strengthened/ reconstructed and improved in 2010-11. Under the **Pradhan Mantri Gram Sadak Yojan**, which is now a part of **Bharat Nirman Scheme**, 710 kms of rural road have already been improved during the current year at a cost of Rs. 239 crore. The PPP project for improvement of the Gurgaon-Faridabad and Ballabgarh-Sohna road has already been taken up on BOT (Toll) basis with a negative grant of Rs. 150.30 crore. The NCR Planning Board has sanctioned road projects worth Rs. 638 crore this year.

30. Steady progress has also been made in the construction of Road over-bridges. 55 ROB's have been sanctioned by the Government, 16 ROB's have been opened to traffic, and 13 are under construction. to provide further impetus to road infrastructure development, the 2nd Phase of the **Rajiv Gandhi Bridges & Road Infrastructure Program** has been taken up with an increased outlay of Rs. 5000 crore. Work is going on for completion of 75 km length of **Rohtak-Jhajjar-Rewari Railway Line** and 88 km long **Sonepat-Jind Railway Line**. These works, costing Rs. 596 crore, are under execution on 50:50 sharing basis with Indian Railways.

31. During this year, 114 public building have been completed at an approximate cost of Rs. 215 crore. Work is going on in 700 building works having an approximate cost of Rs. 1500 crore. Special attention is being given to maintenance and upkeep of public assets.

32. I am allocating Rs. 1938.95 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 1311.97 crore on Plan side and Rs. 626.98 crore on Non-Plan side.

IRRIGATION

33. Speaker Sir, the Department of Irrigation will be completing a number of important projects during the coming financial year. The 70 km long **NCR Water Supply Channel** for carrying drinking water supply to Gurgaon, Manesar, Bahadurgarh, Sampla and Badli will be completed by June, 2010 at a cost of Rs. 322 crore. **Kaushalya Dam** on the Ghaggar River in Panchkula district will be completed at a cost of Rs. 180 crore. **Carrier Lines Channel** for the supply of drinking water to Delhi, and the second phase of **Sahabad-Dadupur-Nalvi Project** will also be completed in the ensuing year. The capacity of **Western Jamuna Canal Main Line** has been increased from 13500 causes to 19557 causes. Recharge channel for **Massani Barrage**, deepending of **Ottu Lake** and **Bhindawas Lake** are the other projects under implementation. To alleviate the problem of water scarcity in the backward area of Mewat, a detailed report is under preparation for construction of the **Mewat Canal**.

34. Water is an important resource, and we are a water deficit State. The present water irrigation requirement of the State is around 36 million acre feet (MAF), whereas the surface and ground water levels in the Bhakra Dam and Pong Dam reservoirs did aggravate the problem of low water availability for our State. Our focus, therefore, has to be on saving water losses by all means, and ensuring optimal and equitable deployment of available water resources. During the next year, we propose to undertake construction of 500 new lined water courses and rehabilitation and remodeling of more

than 500 minors and distributaries in the State, many of which were constructed more than 20 years ago.

35. I am allocating Rs. 1616.49 crore for this sector during 2010-11 which includes Rs. 768.11 crore on plan side and Rs. 848.32 crore on Non-plan side.

INDUSTRIES AND COMMERCE

36 Haryana has emerged as a favoured investment destination in northern India for industry, and scores amongst the top States in India on per capita investment performance. provision of quality infrastructure following the industrial model township (IMT) approach has been a key factor in this performance. Our future plans include expansion of IMT, Manesar, development of an IMT near Roz-ka-Meo and an IMT near Kharkhauda. The projects for development of an IMT at Faridabad, Phase-II of IMT Rohtak, phase-IV of Growth Centre Bawal, Manakpur, Barhi and Panipat are under process. Establishment of an IMT in district Ambala is also under consideration. The HSIIDC proposes to invest over Rs. 1200 crore on land acquisition and development of industrial infrastructure during the ensuing year.

37. **Delhi Mumbai Industrial Corridor Project (DMICP)** is being developed along the alignment of the Delhi Mumbai freight corridor. A multimodal Logistic Hub, an Exhibition cum convention Centre and a Mass Rapid Transport system from Gurgaon to Bawal have been identified as the early bird projects under this mega project. Under the Economic stimulus Package, special dispensation is being made for creation of housing stock for industrial workers.

38. To equip our own people to reap the advantage of industrialization, our Government is establishing a number of skill development facilities. These include the **National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM)** at Kundli, **Footwear Development and Design Institute** at IMT Rohtak, **Central Institute for Plastic Engineering and Technology (CIPET)** at Murthal, and **Indian Institute of Corporate Affairs** at IMT Manesar. I am confident that the various steps taken by the Government for development of infrastructure, improved power availability and congenial labour relations, along with a new industrial Policy, would take the State to new investment horizons.

39. I am allocating Rs. 164.06 crore for this sector during 2010-11 which includes Rs. 125.61 crore on Plan side and Rs. 38.45 crore on non plan side.

INFORMATION TECHNOLOGY AND e- GOVERNANCE

40. Alongside the overall industrial investment, Haryana has emerged as a preferred investment destination for the IT industry, out of a total of 46 SEZs that have been formally approved for the State of Haryana, 35 are in the IT sector, in addition the state has granted licenses to 27 proposals for the establishment of IT/Cyber Parks. Software exports from Haryana have exceeded Rs. 21000 crore during 2008-09.

41. Our state is among the leaders in the establishment of information technology infrastructure under the national e-Governance plan. The state wide area network

has already been set up. The **State Data Centre** is going to be established in the ensuring year. We are taking concrete steps to leverage the use of information technology in governed. Major e-governance projects are under implementation in the food and supplies department, transport department, commercial taxes department and treasuries. We propose to create a cadre of it professionals in the state for smooth implementation and sustenance of e-governance initiatives in the state.

42. I am allocating Rs. 19.59 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 19.35 crore on plan side and 0.24 crore on non plan side. There will be substantial additional investment by the line departments on their individual e-governance initiatives.

TRANSPORT

43. The vision of our e-Government to make Haryana a model state with fast, equitable and inclusive development. Therefore, we lay as much emphasis on improving citizen services across the state as we do on creation and up gradation of infrastructure for economic growth. In order to provide reliable, safe and efficient passenger transport services to each and every village in the state, a **comprehensive passenger transport policy** is being formulated. The policy aims at setting up a state-wide network of bus services, comprising both private service operators and Haryana roadways. To promote safety in the state, **Institutes of Driving Training and Traffic Research** are being established in collaboration with auto majors such as Maruti

Suzuki, Ashok Leyland and Tata Motors at Rohtak, Kaithal and Bahadurgarh.

44. To meet the needs of our citizens, our Government intends to increase the total fleet strength of Haryana roadways to 4500 buses by the end of the 11th plan period. Special attention is being paid to inter city transportation and a **City bus Service** is proposed to be setup under PPP mode in Gurgaon. The Faridabad-Gurgaon-Delhi bus service has recently been started under JNNURM. We also propose to construct Multi-model Hubs/Modern Bus Stands under PPP mode at 20 locations in the State.

45. I am allocating Rs. 1142.10 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 92.72 crore on plan side and Rs. 1049.38 crore on Non plan side.

AGRICULTURE AND ALLIED SECTORS

46. Sir, this sector continues to be the mainstay of livelihood for a majority of our population. The great progress made by our state in the sector is reflected in our food grain production, which has increased six fold from 25.92 lakh tons at the inception of Haryana in 1966-67, to a record 161.66 lakh tons during 2008-09. The weak monsoons this year have led to a marginal reduction in the cultivated area under both Kharif and Rabi crops. However, due to the efforts of our farmers and the Government, there is no reduction in production and we are likely to achieve the target of production of 167.14 lakh tons during the current year.

47. The consumption of fertilizer has touched 14.35 lakh MT and is 11.24% higher than last year's consumption.

However, declining soil health is a matter of concern for us, and micronutrients play an important role in soil fertility. Hence, the Agriculture Department has prepared a new plan scheme for managing micronutrient deficiency, in which 50% subsidy will be provided for micronutrients fertilizer up to a maximum of Rs. 500/- per hectare with a ceiling of 2 hectares per farmer. Various other schemes for restoring soil health and increasing agricultural production will continue in the ensuing year.

48. Keeping in view the interest of the farmers, the State Government has fixed the basic cane price of early, mid and late maturing varieties of sugarcane at Rs. 185/-. Rs. 180/ and Rs. 175/- per quintal, respectively, during the current crushing season which is the highest State Administered price in the country. In addition, our cooperative sugar mills have give4n a bonus of Rs. 25 per quintal. The Shahabad, Karnal and Panipat sugar mills have further shared their profits with the farmers by giving an additional bonus of Rs. 40, Rs. 30 and Rs. 20 per quintal respectively. To enhance sugarcane production in the State, a **Technology Mission on Sugarcane** is proposed by our Government for 2010-11. Moreover, the basic cane prices for early, mid and late varieties have been further enhanced respectively to Rs. 210/-, and Rs. 200/- per quintal for the crushing season of 2010-11. The bonus will be decided before the crushing season commences.

49. To protect our farmers from the vagaries of nature, a new insurance scheme called **Weather based Insurance Scheme** has been conceived to compensate yield loss due to adverse weather conditions. The scheme is being

implemented on a pilot basis for wheat crop during Rabi season 2009-10 in Ambala II, Bubain and Tohana Blocks.

50. Animal Husbandry and Dairying are in integral part of our agrarian economy, and the Government is fully conscious of its contribution to the prosperity of our farmers. A network of 2789 Veterinary Institutions caters to the 90.93 lakh strong livestock population of the State, Efforts will be made to open 80 new Veterinary Institutions during 2010-11. One pet animal medical centre-cum-teaching hospital has been set up at Panchkula and super specially poly clinics have been established at Sonapat and Bhiwani. Another such poly clinic is being setup at Sirsa. The Haryana Dairy Development Cooperative Federation is providing procurement, processing and marketing support to the 5100 dairy cooperatives in the State. Sir, you will be happy to know that farmers are being paid Rs. 340 per kg fat for milk at present. whereas they were being paid a mere Rs. 165 per kg fat in 2005.

51. The cooperative movement has played a pivotal role in supporting the agriculture and allied sector in the State. Over 35 thousands Cooperative Societies of different structure at the grass root level has been restricted by amalgamating 2441 Primary Credit Cooperative Societies into 620 primary agricultural cooperative societies. Under the **Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme** of Government and marginal farmers, while 200734 other farmers have been provided a relief of Rs. 343.16 crore under the scheme.

52. In March 2009, our Government slashed the rate of interest on crop loans from 11% to 7%. The State

Government is giving an interest relief of 2% on timely repayment of crop loans, while the Government of India is paying an interest relief of 1%. With these interest subventions, the effective rate of interest on crop loan is now just 4%. For long term non-agricultural loans, the state Government has increased interest subvention from 3% to 5% under the **Timely Repayment Incentive Scheme**, which has been extended upto 31-12-2010. Moreover, our Government has also modified the provision in the **Haryana Cooperative Societies Act, 1984** under which cooperative loans were recovered as arrears of land revenue. Henceforth, no farmer in the State can now be arrested for recovery of cooperative loans. This Hon'ble Speaker Sir shows how deeply our Government respects the dignity of our farmers.

53. The state Government has set up the **State Compensatory Affrication Fund Management and Planning Authority (State CAMPA)** in accordance with the guidelines of the Government of India. This Fund will be utilized for the protection and management of natural forests and wildlife sanctuaries, compensatory forestation, environmental services and research and development. Under the Forest (Conservation) Act, 1980, a contribution of Rs. 187.43 crore has already been made to this fund by the User agencies against sanctioned proposals.

54. I am allocating Rs. 1073.62 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 540.66 crore on Plan side and Rs. 532.96 crore on Non Plan side.

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATS

55. Our Government will continue its focus on the development of the rural areas. A number of schemes are being implemented, both in the Central and State sectors, for up gradation of rural infrastructure, employment generation and alleviation of poverty as well as other pressing issues. Under the **Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme**, a sum of Rs. 78.79 crore has been utilized up to the end of January, 2010 for generating 39.68 lakh persons-days of employment in the rural areas of the State. Assistance of Rs. 18.40 crore has been provided to 11851 swarozgaris under the **Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana**. To further promote self-employment, **Rural Development and Self-employment Training Institutes** are being set up in existing ITI campuses in five districts. Under the **Indira Awaas Yojana** (IAY) Scheme, 15604 houses have been constructed and 6309 houses are under construction in the current financial year. **Backward Regions Grant Fund** scheme is being implemented in Mahendargarh and Sirsa districts to bridge critical gaps in village infrastructure and facilities.

56. Our Government is providing free residential plots of 100 sq. yard each to eligible scheduled Caste, Backward Class (a) and Below Poverty line families in planned and developed lots under the **Mahatma Gandhi Gramin Basti Yojna**. Out of 6 lakh identified eligible families, 2.91 lakh families have been allotted plots in the first phase in villages where panchayat land was available. The remaining villages will be covered in the second phase. Villages having more than 50% SC population are being provided basic infrastructure under the **Mukhya Mantri Anusuchit Jaati**

Nirmal Basti Yojna. In the first phase Rs 117.85 crore has been released for taking up 442 works in 391 villages. **Mukhya Mantri Sanitation Incentive Puraskar Yojna** has been launched to provide incentive to panchayats for improving cleanliness and eradicating the practice of open defecation in the villages.

57. I am allocating Rs. 956.17 crore for this sector during 2010-11 which is 7.09% higher than the allocation for the current year. This includes Rs. 613.54 crore on Plan side and Rs. 342.63 crore on Non-Plan side.

URBAN DEVELOPMENT

58. Sir, I have already mentioned the great importance that our Government gives to the improvement of infrastructure and facilities in urban areas. The financial position of many of the urban local bodies is weak, and the economic slowdown has further affected their finances. In order to provide a steady source of income to our local self Government entities, I propose to impose a small surcharge on VAT in the State. Out of the collections under the surcharge, 80% will be given to Urban local bodies and 20% will be given to village panchayats. This will help these local bodies take up new development projects in their areas on a sustained basis.

59. City development Plans (CDP) of 73 towns has been prepared to map their basic infrastructure gaps and needs. Under the **Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission** (JNNURM) of the Government of India. Rs. 823.33 crore has been sanctioned for 7 projects for Municipal Corporation, Faridabad. Now, Panchkula has also been included under

JNNURM and its CDP is under consideration of the Government of India. Under the **Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT)**, new projects for integrated solid waste management at Rohtak, Karnal, Indri, Yamunanagar & Jagadari and projects for Sewerage System & Sewerage Treatment Plant at Bahadurgarh Phase-I and Phase-II, Ambala Sadar, Narnaul and Charkhi Dadri have been sanctioned for Rs. 164.07 crore. Under the **Integrated Housing and Slum Development Program**, 16608 dwelling units are being constructed for slum dwellers.

60. To ease the mounting pressure on infrastructure in the mega cities like Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, Hyderabad, Bangalore and Ahmedabad, the Government of India has launched a centrally sponsored scheme called **Urban Infrastructure Development in Satellite Town**. The scheme aims at developing satellite towns near the mega cities as counter magnets by upgrading urban infrastructure facilities such as transport, drinking water, sewerage, drainage and solid waste management. The Government of India will bear 80% of the cost of the scheme, while the balance will be equally shared by the State and the urban local body. The scheme will be implemented in Sonapat town for which a provision of Rs. 100 crore is proposed for 2010-11.

61. I am allocating Rs. 1447 crore for this sector, which is 26.50% higher than the allocation for the current year. This includes Rs 1324.83 crore plan side and Rs. 122.31 crore on non plan side.

SCHOOL AND HIGHER EDUCATION

62. Education is the cornerstone of development, and our insurance for the future of the state. its critical importance and centrality to human resources development cannot be over-emphasized. Speaker Sir, this Government is committed to making education universally accessible and inclusive for all sections of the society. The Hon'ble members would be happy to know that now, in Haryana, a primary school is available to a child within a radius of 1.03 km, a middle school within 1.07 km, a high school within 1.52 km and a senior secondary school with 2.28 km. This Government has upgraded 21 middle schools to high schools and 53 high schools to senior secondary schools. Our seriousness in this sector can be gauged from the fact that the total budget of the education department, which was Rs 1733.18 crore in 2004-05, has gone up to Rs. 5331.35 crore in Revised Estimates 2009-10.

63. We do realize that reaction of infrastructure, though necessary, is by no means sufficient for quality education. A number of schemes are being run by the State and the Centre to attract children to schools and to retain them. These include the **Mid-day Meal Scheme**, the **Rajiv Gandhi Scholarship scheme** and other scholarship schemes. **Monthly incentive Schemes, Cash Awards Scheme.** and others. The **Sarva Shiksha Abhiyan** (SSA), implemented in financial partnership with the Central Government, has been instrumental in improving the quality of elementary education by provision of teachers, opening of schools and alternate school facilities, quality improvement programs and creation and improvement of infrastructure. Following the success of SSA, with the intention of making quality secondary education

available, accessible and affordable to all young persons in the age groups 14-16 years, the Government of India has launched the **Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan**. The RMSA is funded by the Centre and State Governments in the ratio of 75:25 and provides for various improvement schemes on the pattern of Sarv Shiksha Abhiyan.

64. To improve female literacy, the **Saakshar Bharat Scheme** of the Government of India has been launched in Karnal district this year. The scheme will subsequently be extended to 9 more districts having 50% or less adult female literacy. namely Kaithal, Jind, Fatehabad, Hisar, Sirsa, Bhiwani, Gurgaon, Mahendergarh and Faridabad.

65. Higher Education has a different set of challenges and issues from School Education and is critical to qualitative social growth of the State. To ensure closer attention and a sharper focus on its development, our Government has created a separate administrative department of Higher Education. For expansion of outreach, one Central university at Mahendergarh and two private universities have already become operational. More private universities are at advanced stages of being set up. BPS Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonapat will be further improved and strengthened. A number of schemes are also being implemented to enable children from weaker sections of the society to acquire higher education.

66. Teaching activity in schools gets disrupted every month with the retirement of teachers. In order to avoid such disruption, our Government has taken a historic decision to

re-employ retiring teachers till the end of the academic session.

67. I am allocating Rs 5946.29 crore for this sector during 2010-11. which is 11.53% higher than all allocation for the current year. This includes Rs. 1490.32 crore on plan side and Rs. 4455.97 crore on non plan side.

TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION

12:00 बजे

68. Quality technical and professional manpower is the most important resource for the socio-economic development of a State. At the time of its inception, Haryana had only 6 polytechnics and one engineering college in the State with a total annual intake of 1341 students. Now, 112910 students pass out every year from 546 institutions, including 141 engineering colleges.

69. The network of technical institutions is continuously growing. 6 new Government polytechnics have become operational at Madalpur (Faridabad), hathikund Barrage (Yamunangar), Meham (Rohtak), Basai (Gurgaon), India (Mewat) and Mandkola (Mewat). Seven more polytechnics are being opened in Rewari, prestigious **Indian Institute of Management** (IIM) is to be set up in 213 acres of land at village Gharnavati in Rohtak.

70. To prepare our students for skilled industrial jobs, a network of 109 Government industrial training institute and 74 private industrial training centres is operating in the State with an annual intake of 27792 and

10976 students, respectively. 26 new ITS's will be opened in the next three year, while 22 existing ITI's will be expanded. Besides, 29 ITS's and 1500 skill development centres will be established in PPP mode in the State during the next five years.

71. I am allocating Rs. 431.12 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 300.11 crore on Plan side and Rs. 131.01 crore on Non-plan side.

HEALTH

72. One of the key functions of a democratic Government is to provide reliable, affordable and accessible healthcare to its citizens. This Government is striving hard to improve the quality of health infrastructure, the availability and quality of doctors, availability of free medicines, and efficient delivery of health and medical services, The state is providing healthcare through 52 hospitals, 94 Community health centres, 441 primary health centres, 2465 health sub-centres, 20 district TB hospital and 51 dispensaries. Free drug supply to all the patients and introducing the Surgery package program are among the major initiatives of the health department. Six district hospitals at Gurgaon, Hisar, Bhiwani, Faridabad, Sonapat and Rohtak are being upgraded into state of the art Multi Specially Hospitals with an expenditure of more than Rs. 102 crore under the Economic stimulus package. Three district hospitals at Rewari, Panipat and Panchkula will be upgraded and Civil Hospital at Dadri will be expanded to 100 beds during 2010-11.

73. Construction of two medical colleges at Khanpur Kalan (Sonapat) and Naihar (Mewat) has been started under the Economic Stimulus Package at an estimated cost of Rs. 617.61 crore. The Government has also announced setting up of **Kalpna Chawla Medical College** at Karnal. **Pt. B.D. Sharm Post Graduate Institute of Medical Studies**, Rohtak is to be upgraded to the level of All India institute of Medical Studies under the **Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojna**. For this purpose, a sum of Rs. 125 crore has been earmarked by the Government of India and Rs. 25 crore will be contributed by Haryana.

74. On 26 January, 2010, our Government launched the **Nehru Bal Drishti Yojana** a new scheme under which eye collection centres have been set up and linked to “**102**” services in each district. At present one Eye Bank exists in the State at PGIMS Rohtak. We propose to set up another **Eye Bank** in the State in the ensuing year.

75. I am allocating Rs. 1125.48 crore for this sector during 2010-11 which is 6.07% higher than the allocation for the current year. This includes Rs. 455.85 crore on Plan side and Rs. 669.63 crore on Non plan side.

SOCIAL WELFARE

76. Haryana Government is fully committed to the welfare of the vulnerable sections of the society and has undertaken a series of effective steps to provide social security to the aged, widows, destitute women, handicapped persons, eunuchs, dwarfs, persons from minority communities and families with only girl child/children. A provision of Rs.

1465.46 crore has been made for these schemes for the current year.

77. To ensure that citizens with disabilities are not left out of the mainstream of development, our Government has launched an ambitious **Jawahar Social Infrastructure Mission** to take up projects for this section of our society. Under JSIM we propose to set up 10 schools for the visually challenged children & 8 schools for the children, three state level institutes for providing vocational training to persons with different physical disabilities, 4 Senior Citizens homes, 21 vocational training centers and two life long homes for the differently abled persons in the next three years at the cost of Rs. 150 crore.

78. In order to encourage scheduled caste girl students to go for higher education, a new scheme namely **Anusuchit Jati Chhatra Ucch Shiksha Protsahan Yojana** has been launched for the year 2009-2010 wherein annual scholarships ranging from Rs 5000 to 14000 are being provided to Scheduled Caste girl students studying science, commerce or professional courses. **Dr. Ambedkar Medhavi Chhatra Yojana** has been extended to post graduate classes. The popular Ladli scheme for supporting the second girl child, initially launched for five years, has been extended for another five years.

79. I am allocating Rs. 2167.15 crore for this sector during 2010-11, which includes Rs. 2010.20 crore on Plan side and Rs. 156.95 crore on Non Plan side.

RECRUITMENT IN Government

80. In a democratic setup, the Government is a vehicle for the delivery of development, infrastructure and social services to the citizens. Therefore, the efficiency of the Government as an organization, as well as the bottlenecks in its operations, assumes importance. One of the main bottlenecks in Government functioning at present is the delay and inconsistency in recruitment of human resource. We have, therefore, identified the services and cadres which need frequent recruitment to meet the requirements of different departments, public undertakings, boards and corporations, and decided that the Haryana public service commission and the Haryana staff selection commission will hold annual examinations, at pre determined dates, for recruitment thereto, so that the candidates do not have to apply time and again. According the HPSC will annually conduct the Engineering services combined examination, agriculture and allied services, combined examination and legal and allied services combined examination, whereas the HSSC will conduct graduate level combined examination, junior engineers and allied services combined examinations, clerk grade examination, drivers combined test and steno typist stenographer combined examinations.

81. Basic minimum eligibility qualification in respect of similar category posts shall be uniform in all departments, boards, corporations, companies and societies. there shall be a uniform application form in computer readable format. Self certified copies of certificates relating to caste, residency, age physical handicap etc. will be accepted at the application stage. Original certificates shall be checked

only at the time of interview and joining of selected candidates.

82. We have also decided that all fresh recruits will undergo mandatory induction training for 3 months after joining so that they are well prepared for their respective jobs. They will be given postings only after completing such induction training.

BUDGET ESTIMATES 2010-11

83. Sir, I would like to draw the attention of Hon'ble members to the fact that the budget estimates I bring before this august House for voting this year are in a slightly modified form. You will notice, Sir, that this time we are proposing 45 demands for grants as against the traditional 25 demands. Recognizing that the state expenditure pattern has undergone significant changes in the last few years. the clubbing of departments under various demands has been rationalized. This has been done to streamline departmental spending, and to bring greater transparency, accountability and control in the budget. It would also instill greater discipline in matters of re-appropriation and avoid large variations between the budget provisions and actual expenditure. The Hon'ble members will also get a clearer picture of the expenditure they are voting on.

84. I now proceed to present before this august House the Budget estimates for the financial year 2010-11. The financial year 2009-10 opened with a deficit of Rs. 602.41 crore as per RBI books and is likely to be closed with a deficit of Rs. 634.06 crore representing a transaction deficit of Rs.

31.65 crore during the year on annual account. Under the Budget Estimates 2010-11, the Total Receipts (net of Public Debt) are projected at Rs. 30085.98 crore, of which Revenue Receipts are Rs. 24540.83 crore, while Capital Receipts (net of Public Debt) are Rs. 5545.15 crore. These signify, respectively, an increase of Rs. 1729.05 crore, Rs. 1538.93 crore and Rs. 190.12 crore over the corresponding projections in the Budget Estimates 2009-10. The total expenditure (excluding repayments) under the budget estimates 2010-11 is projected at Rs. 33600.84 crore of which revenue expenditure is Rs. 28482.64 crore, while the capital expenditure is Rs. 5118.20 crore. These signify, respectively, an increase of Rs. 2004.73 crore, Rs. 1818.49 crore and Rs. 186.24 crore over the corresponding projections in the Revised estimates 2009-10. The budget estimates 2010-11 project a revenue deficit of rs. 3941.81 crore and a fiscal deficit of Rs. 8815.64 crore. The balance form current revenues for 2010-11 is projected to be Rs. 845.82 crore. The revenue deficit is primarily on account of the impact of the 6th pay commission, with the annual pay increase impact for 2010-11 amounting to about rs. 2600 crore, and the arrears of pay and pension amounting to about Rs. 1570 crore.

85. Hon'ble members would be glad to note that our Government has made investments on capital expenditure to the tune of Rs. 17879 crore between 2005-2010. Compared to the capital expenditure of only Rs. 8308 crore during 2000-2005. This Government speaker sir is totally dedicated to creating a bright future for our state.

86. let me now indicate the sectoral allocation in the budget estimates 2010-11. The agriculture and allied sector is slated to receive rs 1073.62 crore, the power sector is slated to receive Rs. 4642.71 crore, the transport sector is allocated rs 1142.10 crore, the irrigation sector is projected to receive rs 1616.49 crore, the water supply and sanitation sector is slated to receive rs 1297.69 crore, the urban development sector is allocated rs 1447.14 crore, the education sector including industrial training and technical education, is projected to receive rs 637.41 crore, the health sector is slated to receive rs 1125.48 crore, the social justice and empowerment including welfare of scheduled castes and backward classes sector is allocated rs 2167.15 crore, and the rural development and panchayat sector is slated to receive rs 956.17 crore.

87. As against the annual plan projections in the budget estimates 2009-10 at Rs. 10000/- crore, revised further to Rs. 10400 crore, the allocation for the annual state plan 2010-11 is proposed at Rs. 10500 crore. in addition to it, an outlay of rs 1363.58 crore for the centrally sponsored schemes and other development plan schemes has also been included on the plan side, boosting the composite plan outlay in the budget estimates 2010-11 to rs 11863.58 crore.

88. Let me confess sir that the decision to come before this august house with a revenue deficit budget this year was not an easy one. it would have been an easy escape route for me to prepare a budget without deficit by suppressing expenditure. But the collective conscience of this Governemnt does not allow such populist measures at the

expenses of the future of our people. It was a conscious decision of our Government not to curtail investment expenditure on the ongoing projects and important projects in the pipeline, in the long term interest of this state, and we have targeted a modest increase in plan spending for our Annual Plan 2010-11 accordingly. We do propose to exercise economy and restraint in general expenditure in the Government departments, and indeed, our Government has already adopted significant economy measures, but the pace of development of Haryana has to be maintained at all cost.

89. Our effort in this budget has been to consolidate the gains that have been made by the state in the last five years. The budget deficit is within manageable limits and the measures for further financial discipline are likely to reduce its pitch further. Our tax revenue has already started recovering its normal growth, and can be expected to exceed the modest targets kept in the budget proposals. It is also expected that the share in central taxes and other devolutions would go up during the year, as the implementation of revised pay structure across the country and payments of arrears are sure to increase the income tax receipts of central Government. I, therefore, feel confident in assuring the House that we will be able to implement all our projected programs very successfully while achieving the targets fixed in the Budget. For this I solicit active cooperation and support of all the Hon'ble members of this august House, and through them, of all the proud citizens of Haryana.

CONCLUSIONS AND COMMENDATION

90. Before I conclude, I would like to acknowledge the untiring efforts and dedication put in and exhibited by the Finance Secretary and his colleagues in the Finance Department and the National informatics Centre and its employees who preserved day and night to help me prepare and present these budget proposals.

91. Hon'ble Speaker Sir, through you I want to extend the most solemn assurance to this House and to the people of Haryana at large, that we would summon all resources available to us and dedicate ourselves to the task of taking Haryana forward on the path of development at the same pace with the same zeal that we have shown in the last five years.

92. Sir, with these words now I commend the Budget Estimates 2010-2011 to this House for its consideration and approval.

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसे निर्णय भी लेने जरूरी होते हैं जो कि समस्त जनता के हित को ध्यान में रख कर लेने होते हैं क्योंकि ऐसे निर्णय ही हमें नया अनुभव और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। अंत में मैं कहूंगा:

क्यां डरे हम जिंदगी में क्या होगा,

कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा।

Sir, with these words now I commend the budget estimates 2010-2011 to this House for its consideration and approval.

JAI HIND

Mr Speaker: The house stands adjourned till 10:00 A.M on Thursday, the 11th March 2010.

12:24 hrs.

(The sabha then adjourned till 10:00 A.M on Thursday, the 11th March, 2010.)